

tion Limited, for the year 1969-70, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon, under sub-section (1) of section 619A. of the Companies Act, 1956. [Placed in library. See No. LT-4051/72]

FERTILISER (CONTROL) THIRD AMENDMENT ORDER 1972

SHRI ANNASAHEB SHINDE: Sir, I also beg to lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture) Notification G.S.R. No. 428 (E), dated the 26th September, 1972, publishing the Fertiliser (Control) Third Amendment Order, 1972, under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 [Placed in Library. See No. LT-3963/72.]

NOTIFICATION UNDER THE ESSENTIAL COMMODITIES ACT, 1955.

SHRI ANNASAHEB SHINDE : Sir, I also beg to lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture) Notification G.S.R. No. 428(E), dated the 6th October, 1972, under sub-section (1) of section 12A of the Essential Commodities Act, 1955. [Placed in Library. See No. LT-3963/72.]

ANNUAL REPORT OF THE DEVELOPMENT COUNCIL FOR SUGAR INDUSTRY FOR THE YEAR ENDING THE 31ST MARCH 1972

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (PROF. SHER SINGH) : Sir, I beg to lay on the Table, under sub-section (4) of section 7 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, a copy (in English and Hindi) of the Annual Report of the Development Council for Sugar Industry for the year ending the 31st March, 1972. [Placed in Library. See No. LT-3964/72.]

MOTION FOR ELECTION TO THE NATIONAL FOOD AND AGRICULTURE ORGANISATION LIAISON COMMITTEE.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB SHINDE) : Sir, I move :

That in pursuance of the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture) Resolution No. F. 10-1/65-FAIT, dated the 9th September, 1966, as amended, this House do proceed to elect in such manner as the Chairman may direct, one member from among the members of the House to be a Member of the National Food and Agriculture Organisation Liaison (Committee).

The question was put and the motion was adopted.

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE BILL, 1970—Contd.

श्री नवल किशोर (उत्तर प्रदेश) :

उपाध्यक्ष जी, कल इस विधेयक के वाद-विवाद के संबंध में मैं यह कह रहा था कि आज हिन्दुस्तान की आजादी के 25 साल के बाद भी यह एक अफमोस की बात है और एक दुख की बात है कि पुलिस के प्रति आज भी जनता में वह विश्वास पैदा नहीं हो सका है जो कि किसी आजाद देश के अंदर होना चाहिए। श्रीमन्, जिस समय हम आजादी की जंग लड़ रहे थे, उस समय हममें से बहुत से लोगों का और जनसाधारण का वास्ता पुलिस से पड़ा था और आज 25 साल के बाद भी उस समय की जो धारणायें थीं वह समाप्त नहीं हो पायीं हैं। इस में शक नहीं कि बहुत से कमीशन बैठे इस पुलिस के संबंध में, इसलिए कि उसमें सुधार किया जाय—उत्तर प्रदेश में कमीशन बैठा, राजस्थान में कमीशन बैठा, और शायद और दूसरे स्टेट्स में भी कमीशन बैठे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई विशेष सुधार पुलिस की जहनियत में, उसके अप्रोच में, उसके काम करने के तरीकों में हम अभी तक पैदा नहीं कर सके। आज भी ग्राम तौर से सदन में इस बात की शिकायतें आती हैं और जब कभी यहां ला एंड आर्डर की बात आती है और कहीं पुलिस से कंफ्रंटेशन होता है तो उसके सिक्सिसे

[श्री नवल किशोर] में पुलिस की निन्दा की जाती है। तो मैं इस तरफ गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उनका तमाम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट होती है, उस पर आधारित है। पुलिस शासन की वही बुनियाद है। लेकिन आज भी फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट को लिखने का वही तरीका है। आज भी थानों की जो फीस पहले थी, उससे वह कुछ बढ़ गयी है, लेकिन एफ० आई० आर० की फीस अपनी जगह कायम है और मिर्धा जी मुझ से ज्यादा जानते होंगे कि एफ० आई० आर० लिखी नहीं जाती है, बल्कि वह लिखवाई जाती है। जो आदमी जाता है अपनी शिकायत लिखवाने के लिए वह अनभिज्ञ होता है कानून से और थाने के दीवान जी जो होते हैं, जो पुलिस के सबसे बड़े हाकिम हैं थाने पर, वह जिस तरह से चाहते हैं उस रिपोर्ट को लिख लेते हैं। यह बात सही है कि आपने अब उस में कुछ तरमीम की है, उसकी अब कापी फ्री दी जाएगी, वैसे कापी की बाब तो अभी भी थी, लेकिन अब शायद बिना पैसे के कापी दी जायगी, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। पहले लिया जाता था या नहीं, इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन उसमें कोई खास सुधार होने वाला नहीं है। आज भी यह बात सब पर जाहिर है कि जो आदमी रिपोर्ट लिखाने आता है, उसकी रिपोर्ट में पुलिस दूसरे लोगों को फसाने की कोशिश करती है और आज भी लोगों पर झूठा केस बनाया जाता है। और आज कल थानों में एक खाम बाब यह है कि दफा 19 आर्म्स ऐक्ट का इस कदर मिसयूज होता है कि कुछ कहना नहीं। किसी भी बेगुनाह इंसान का देशी तमंचा रखवा कर उसका चालान कर दिया जाता है और इसी तरह के झूठे केसेज बनाये जाते हैं। इसके

पीछे कुछ पार्टीबाजी होती है। वहां के गांव की और शहरों की भी और कुछ पोलिटिकल असर से भी ऐसा होता है। तो मैं यह बात जानना चाहता हूँ कि इतनी मेहनत के बाद भी इस एफ० आई० आर० में सुधार लाने के लिए आपने क्या कोई बात की है? शायद कुछ नहीं हुआ है। श्रीमन्, मिर्धा पाहब होम मिनिस्टर है। वह इस बात को जानते होंगे कि आज भी सिर्फ 60 परसेंट केमेज की एफ० आई० आर० लिखी जाती है और 40 परसेंट केमेज की नहीं लिखी जाती है। श्रीमन्, जब हम उत्तर प्रदेश में थे, तो वहां इस बात की कोशिश की गयी कि कोई भी रिपोर्ट छिपायी न जाय, क्योंकि पुलिस एफ० आई० आर० इसलिए नहीं लिखती है ताकि उसके यहां क्राइम्स के आंकड़े कम रहें और उनको यह कहने का मौका रहे कि हमारे यहां पिछले साल के मुकाबले इस साल क्राइम्स कम हुए हैं। हालांकि क्राइम्स कम नहीं होते हैं। वैसे आपने उसमें कुछ अमेंडमेंट किया है और वह बाद में आयेगा और वह बात अपनी जगह पर है कि अगर किसी की रिपोर्ट न लिखी जाय तो वह उसको सीधे सुपरिंटेंडेंट के पास भेज सकता है।

आप जो अमेंडमेंट लाये हैं, उससे स्थिति बहुत नहीं बदलती; क्योंकि ऐसा आज भी है। मैं चाहता हूँ कि अगर यह साबित हो जाए कि थानेदार ने या दीवान जी ने, जो भी अफसर वहां हैं, उन्होंने जान-बूझ कर रपट नहीं लिखी है, किसी वजह से तो उनके लिए पनिशमेंट का कोई न कोई इंतिजाम होना चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूँ। आपने जुडीशियरी और ऐक्जीक्यूटिव को सेपरेट कर दिया। बहुत से स्टेट्स में तो यह था, आपने उसको आल इंडिया बेसिस पर अलग कर दिया, यह अच्छा

कदम है। मैं यह अर्ज कर रहा था कि बहुत दिनों से यह भाग थी कि आपकी पुलिस के दो विंग हॉन चाहिए, एक इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस हो और एक प्राजी-क्यूटिंग पुलिस हो। इसका कुछ ऐक्म-रिमेट हमने उत्तर प्रदेश में भी किया था। अब तो पता नहीं उसका क्या हुआ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मिर्धा साहब इस बात से इत्तीफाक करते हैं कि इसमें यह बात की जाए? श्रीमन्, मैं इस बात को मानता हूँ कि इसमें जो बहुत सी अच्छी तब्दीलियाँ हुई हैं। उनको ले मैं बधाई देना चाहता हूँ, उनको गौर ज्वाइट सेलेक्ट कमटी को। मैंने खा कि बहुत से बच्चों, स्त्रियों और समरी गैलूम के बारे में इसके अन्दर काफी सुधार किये गये हैं। यह भी आपने अच्छा किया है कि आन्तरेरी मजिस्ट्रेट और जस्टिस आफ पीस को खत्म कर दिया।

श्री श्याम लाल यादव (उत्तर प्रदेश)
रुल नहीं हुए हैं, सेकिंग क्लास के होंगे।

श्री नवल किशोर कुछ कम ताकिये हैं। इसमें आपने प्रोवेशन आफ गफेडस ऐक्ट के लिए तथा रिमांड बगैरह के बारे में जो सुधार की बातें की हैं, वह तो ठीक हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसमें जो आपकी दफा 83 है, उसके अन्तर्गत आपने यह किया है कि अगर कोई कोर्ट के सामने पेश न हो तो उसका अब तक कायदा यह था कि 30 दिन तक वह पेश न हो तो उसकी गपर्टी अटैच हो सकती थी। आपने 30 दिन की बात निकाल दी। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी आदमी पर झूठा केस हो जाए और उसकी गपर्टी के अटैचमेंट का आर्डर एक साथ कर दे तो उसको पता भी नहीं चला कि उसके ऊपर केस हुआ है। तो जो सेक्शन 83 का असली मशा या उसको आपने खत्म कर दिया। इसलिए

मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस पर दोबारा दृष्टिपान करें।

श्रीमन्, दफा 107, 108, 109 और 110 ये चारो प्रिवेटिव मेक्शस हैं। लेकिन मिर्धा साहब उतना ही जानते हैं जितना कि मैं जानता हूँ कि इनका मिसयूज होता है। अब तो दिक्कत यह है कि कोई मूवमेंट हो, चाहे जनता का मूवमेंट हो, स्टुडेंट्स का मूवमेंट हो, उनको दबाने के लिए दफा 107, 108, 109 और 110 का मिसयूज होता है। मैं यह समझता था कि आजाद हिन्दुस्तान के अन्दर इन दफाओं के लिए कोई स्थान कोड आफ क्रिगनल प्रोसीजर में नहीं होगा, क्योंकि यह धब्बा है किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए और उस देश के लिए जहाँ डेमोक्रेसी बुनियाद मानी गई है हमारे राजतंत्र की। लेकिन श्रीमन्, मुझे एक बात याद है, आपको भी शायद जेल जाने का सौभाग्य मिला होगा। मिर्धा साहब ओम् मेहता से तो बात होती रहती है, मेरी तरफ भी निगाह करें। I want your attention and also your mind.

मैं अर्ज कर रहा था कि मैं जब जेल में था तो श्रीमन्, जब कभी वहाँ सफाई की कमा होती थी या स्वीपर्स की कमा होती थी तो दफा 109 में भातुओं को भेज दिया जाता था। यह दफा निकम्मी है, It is a black spot on any decent administration. मगर वह आज भी इसमें कायम है। 108, 109 और 110 में आपने इतना कर दिया है कि उसकी प्रोसीडिंग जुडीशियल मजिस्ट्रेट करेगा, मगर 107 में आपने रखा है कि उसका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा। तो कम से कम 107 में इतना तो कर ही दीजिये कि वहाँ भी जुडीशियल मैजिस्ट्रेट करे; क्योंकि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और पुलिस में माठ-गाठ होती है और उससे

[श्री नवल किशोर]

न्याय मिलने में काफी दिक्कत होती है।

श्रीमन्, इसके अन्दर जो पहले कमिटल प्रोसीडिंग्स होती थी, इसको खत्म किया है। यह एक मिक्सड चीज है। इससे एक फायदा यह जरूर होगा कि जो देरी होती थी वह कम हो जाएगी, लेकिन इससे मुझे डर यह है कि सेशन कोर्ट में काम बहुत ज्यादा बढ़ जायगा, क्योंकि कमिटल प्रोसीडिंग में मैजिस्ट्रेट को यह भी अधिकार था कि अगर वह समझता था कि प्राइमार्फेसी केस नहीं बनता है तो वह उसे डिसचार्ज कर देता था। फिर भी डिले को कम करने के प्वाइंट आफ व्यु में मैं समझता हूँ कि यह एक अच्छा कदम है।

श्रीमन्, इसमें जो दफा 407 है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। इसके सम्बन्ध में एक बुनियादी सवाल है। दफा 407 में एप्पीकेशन फार ट्रांसफर की बात थी और एडजर्नमेंट आफ प्रोसीडिंग की बात थी। अब तक कायदा यह है कि अगर कोई आदमी एप्पीकेशन दे दे कि मैं अपने केस को ट्रांसफर कराना चाहता हूँ और हाई कोर्ट को मूव करूंगा तो वह प्रोसीडिंग वही की वही एडजर्न कर दी जाती है। अब जो नया बिल पेश किया है, इसमें इस चीज को हटा दिया है। मगर ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ने इसको पास किया और सर्वसम्मति से पास किया, मगर अब मिर्धा साहब के नाम से एक अमेडमेंट है कि स्थिति फिर वही की वही कर दी जाए। श्रीमन्, मैं आपके जरिये से एक बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूँ। मैं इस बात को मानता हूँ कि कैबिनेट को इस बात की आजादी और अधिकार है कि ज्वाइंट कमेटी के बाद भी वह कोई भी अमेडमेंट करना चाहे तो अमेडमेंट कर सकती है। मैं उस अधिकार का मानता हूँ। लेकिन जिस कमेटी में मिर्धा साहब मौजूद हो—

और मिर्धा साहब चाहे कैबिनेट मिनिस्टर न हो, किन्तु उनकी हैसियत कैबिनेट मिनिस्टर से कम नहीं है—जब उनके सामने ज्वाइंट कमेटी में युनानिमस फैसला हो जाय, तब उसको इस तरह से चेज करना में समझता हूँ कि न कोई उस कमेटी के स्टेचर को यह बढ़ाता है और अगर मुझे माफ करे तो मैं कहूंगा कि मेरे दोस्त मिर्धा जी का स्टेचर भी नहीं बढ़ा है। इसके माने यह है कि कहीं कोई फाइनैलिटी नहीं है। जब हम आप बैठ करके किसी कमेटी में आपस में डेलिबरेशंस के बाद, वाद-विवाद के बाद एक चीज पर आ जाय, वह चीज सर्व-सम्मति से तय हो जाय, तब मैं समझता हूँ कि जो चीज सर्वसम्मति से तय हो जाय, उनके अन्दर इस तरह के अमेडमेंट नहीं आने चाहिए।

इसमें, श्रीमन्, 151 की बात भी आई है। पुलिस की जो मौजूदा हालत है, उसमें दफा 151 में जो पावर मैं आपने दी है, मैं समझता हूँ कि उससे अभी तक जो शकाये हैं लोगों के दिमाग में उसके मिसयूज के बारे में हैं। वह अपनी जगह पर अब भी रहेगी यद्यपि आपने उसके सब-सेक्शन (2) में यह कर दिया है कि बेल की प्रोसीडिंग्स उसी तरह से होगी जैसे कि चैप्टर 5 में व्यवस्था है। मगर चैप्टर 5 उन आदमियों में डील करता है जो कि बर्गर वारेट के पकड़े जाय, मगर आफेंस करने के बाद पकड़े जाय, लेकिन इसमें तो बिना कुछ किए पकड़ सकते हैं सिर्फ उस बिना पर कि आपको शक है कि आफेंस होगा। तो इसका काफी मिसयूज होता है और आगे भी होगा। इतनी मेहनत के बाद भी वह चीज वही है, जहां पर पहले थी।

श्रीमन्, पब्लिक प्राजीक्युटर की बात है, मिर्धा साहब भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ कि ये जो पब्लिक प्राजीक्युटर्स एप्वाइंट

किये जाते हैं वह कैसे किये जाते हैं। आज तक यह कायदा था, आपने यह रखा था अपने बिल में कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और हाई कोर्ट की सिफारिश से उनका एप्वाइंटमेंट होगा, लेकिन ज्वाइट कमेटी ने उस बात को नहीं माना। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि इसके अन्दर काफी पोलिटिकल प्रेशर और काफी पोलिटिकल पैट्रोनेज होता है। जो आपने क्लोज रखा था ओरिजनली वह ज्यादा वेटर था बजाय इसके। इसी तरह से जब आप डिस्ट्रिक्ट कौमजूम को एप्वाइंट करते हैं उसमें यह मेरा अपना एक्स्पेरियंस भी है कि ऐसे वकील जिनके पास कभी एक केस नहीं जाता है, मगर चूँकि उनका पुल होता है कहीं न कहीं मेरे पास या मिर्धा साहब के पास और वह डिस्ट्रिक्ट कौंसिल वन जाते हैं। सिर्फ उनके पास पोलिटिकल प्रेशर होता है और पोलिटिकल स्ट्रिम को वह खींच सकते हैं। तो मैं यह चाहता था कि जो पब्लिक प्रोजेक्ट्युटर की एप्वाइंटमेंट की बात है, वह अपनी जगह जैसी आपने पहले रखी थी बिल में वैसी ही रखनी चाहिए।

श्रीमन्, आज कल जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं they are infact, courts of acquittal. मैंने आकड़े इकट्ठे किये थे जब कि मैं यू० पी० में होम मंत्री था तो मालूम हुआ कि सिर्फ 60 परसेंट कम्प्लेट्स की एफ० आई० आर० लिखी जाती है। उसमें से 60 परसेंट अदम तफतीश में खत्म कर दिये जाते हैं, सिर्फ 40 परसेंट का इन्वेस्टिगेशन होता है। उस 40 परसेंट में 15 परसेंट का काविक्षन होता है। हमारे डिप्टी सेक्रेटरी जज साहब बैठे हैं, इनका भी एक्स्पेरियेन्स होगा। और उन 15 परसेंट में से भी जो अपील में जाते हैं तो छूट-छाट कर 5 परसेंट बच

जाते हैं। आज जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है और जिम तरह से कोर्ट्स का एक्विटल चल रहा है उससे मैं समझता हूँ आप क्राइम्स की गेक्थाम नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, मैं जानता नहीं और मैं यह कहने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आप उसमें अन्तेससरी इन्टरफियरेन्स करें। श्रीमन्, एक नागरवाला का केस था। यहाँ मैं उसके डिटेल में नहीं जाता हूँ, मगर कोर्ट ने प्राम्टनेस और इफिशियेन्सी में कमाल कर दिया—3 घंटे में सब कुछ हो गया, वरना एक-एक साल, डेढ़-डेढ़ साल तक केसेज पड़े रहते हैं मेशन्स कोर्ट में, और मेशन्स कोर्ट में ही नहीं, जो नीचे की लाअर कोर्ट्स हैं, उनमें भी छ-छ 'आठ-आठ' महीने हों जाते हैं। मैं चाहता हूँ, नागरवाला केस की जो इफिशियेन्सी थी हन्ड्रेड परसेन्ट, उसकी 10 परसेन्ट इफिशियेन्सी भी कोर्ट्स में आ जाए तो ये बहुत सारे जो एरियर्स इकट्ठा हो गए हैं कोर्ट्स में, ये एरियर्स आसानी से खत्म हो जाएंगे।

अब मैं आपके जरिफ में कहना चाहता हूँ, अंडर ट्रायल्स के बारे में अक्सर यह होता है कि लोग महीनों अंडर ट्रायल बने रहते हैं। आपने उसमें एक मियाद रखी है छ महीने की, मगर उसमें एक दिक्कत यह है कि मान लीजिए, एक आदमी को आपने बदल कर दिया, वह पहुँच गए जेल में और अगर श्रीमन् उसका आफेंस ही ऐसा है, जिसमें उस मजा 3 महीने या 6 महीने में ज्यादा नहीं हो सकती, तो छ महीने उसके वैसे ही हो गए जेल-खाने में, हालाँकि ऐसे मैजिस्ट्रेट भी हैं जो इनने सेन्टेन्स को सेट असाइड कर देते हैं, उस पीरियड का कंसिडरेशन कर लेते हैं। इसमें आपने इम्प्रूवमेंट किया है, इसमें शक नहीं, लेकिन इसके

[श्री नवल किशोर]

बावजूद भी जो स्थिति है वह इससे सुधरने वाली नहीं है। यह मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ।

बेन्स के बारे में इसमें एक बात यह है कि जो बेलब्ल आफन्सेज है उनको बेल देने के कुछ तो अधिकार पुलिस के होते हैं और कुछ हमारे मजिस्ट्रेट्स के होते हैं, हालांकि कानून यह है कि उसको फौरन बेल द दिया जाए, लेकिन ग्राम तौर पर ऐसा होता है कि पुलिस आफिसर उसको बेल नहीं देता और कभी-कभी मजिस्ट्रेट भी ऐसा करते हैं कि उसको जेल में कस्टडी के अदर भेज देते हैं और उसमें काफी टाइम लग जाता है क्योंकि पेशकार वगैरह कम्प्लेन की बात तो मैं नहीं कहना चाहता—जब तक शायद उनके चाय-पानी का इंतजाम न हो तब तक आगे कोई चीज बढ़ती नहीं। तो मैं चाहता हूँ, स्ट्रिकटली इस बात को फोलो किया जाए कि जो बेलब्ल वारेन्ट्स हैं उनकी फौरन में फौरन उसी दिन बेल हो जानी चाहिए।

श्रीमन्, जूडीशियल मजिस्ट्रेट का एपौ-इन्टमेंट उसमें रखा है हाई कोर्ट के तहत। मैं इस बात में तो इत्तिफाक करता हूँ कि उनका डिस्प्लिन, उनका कोड आफ काउन्ट, उनका ट्रान्सफर, उनकी एफिशियन्सी, उनका प्रमाशन, ये सब हाई कोर्ट के अडर होना चाहिए, मगर जब जजेज का एपौइन्टमेंट भी एग्जीक्यूटिव आर्डर में होता है तो जूडीशियल मजिस्ट्रेट्स का फर्स्ट एपौइन्टमेंट जो है वह एग्जीक्यूटिव से होना चाहिए। ऐसा मेरा अपना खयाल है।

श्रीमन्, अब दो और बातें कह कर मैं खत्म कर दूंगा। क्लॉज 116 में आपने लिखा है—that the date on which the Magistrate starts inquiry after appearance of all

the persons concerned. अब मान लीजिए किसी केस में कई मुलजिम हैं, 6 तो हाजिर हो गए, एक मुलजिम हाजिर नहीं होता या पुलिस मेनिपुलेट करती है एक आदमी हाजिर न हो, तो मेरा कहना यह है कि उस एक आदमी की वजह से वे छ आदमी जेलखाने में मड़ते हैं। यह बात मुनासिब नहीं है। इसलिए मैंने इस तरफ ध्यान खींचा।

इसी तरह में, श्रीमन्, 172 की बात है, क्लॉज 172 जो है, उसमें भी यही बात है और इसमें भी गोलमाल करने के लिए काफी गुजायश है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था और मेरा भी एडमिनिस्ट्रेशन का अपना तजुर्बा है कि आज भी पुलिस की डायरी खाली रहती है और पिछली तारीख में आसानी के साथ रिपोर्ट दर्ज हो सकती है। इस चीज को रोकने के लिए मुझे कोई चीज इसमें दिखलाई नहीं देती है।

उसी तरह से क्लॉज 438 है, जिस के बारे में श्री झा ने इस प्रकार से नोट आफ डिसेट लिखा है:

It cannot be denied that the beneficiaries of this clause will be only moneyed persons. The common man cannot avail of this additional advantage after committing 'non bailable' offence, it is necessary that either this clause is totally deleted or this power of granting anticipatory bails is given to the lower courts, approachable by wider sections of citizens or a proviso should be added excluding charges of murder, smuggling, blackmarketing, defalcation and other economic or heinous offences."

श्रीमन्, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इसमें शक नहीं है कि ज्वाइन्ट सिलेक्ट कमेटी ने बहुत

मेहनत में यह कार्य किया है। इस बिल का ऐम्स एन्ड आब्जेक्ट्स यह है कि स्पीडी ट्रायल हो, गरीबों को जस्टिस मिल सके, ज्यूडीशियरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन हो आल इंडिया बेसिस पर, ये जो चीजें हैं, बहुत अच्छी हैं और इस सम्बन्ध में जो कदम उठाया गया है, उससे जनता को लाभ पहुंचेगा क्योंकि इस बिल में काफी सुधार हो गया है।

मैं यह भी मानता हूँ कि कोर्ट भी कानून कभी भी एक स्टेज या दो स्टेज में परफेक्ट नहीं बन सकता है। मैं इन सब बातों को जानता हूँ कि कानून को अमल करने के बाद ही उसमें सुधार किया जा सकता है। हमारे मिर्धा साहब सम्भवतः एक प्रोग्रेसिव आदमी हैं और मैं समझता हूँ कि उनकी गिनती उनके दल में प्रोग्रेसिव आदमियों में मानी जाती होगी। अगर इसमें प्रिवेन्टिव डिटेन्शन के चेंबर का वह हिस्सा जिसमें 107, 108, 109, 110 और 151 भी आता है, निकाल दिया जाता तो बहुत अच्छा होता। इफ यू वान्ट प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन तब ये चीजें एक ब्लैक स्पॉट हैं। मुझे इस बात का ताज्जुब है कि श्री शुक्ल जी जो इस कमेटी के चेयरमैन थे, उनकी निगाह से यह चीज क्यों बच गई।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (उत्तर प्रदेश):
बहुत कुछ सुधार हुआ है।

श्री नवल किशोर श्रीमन्, आखिर में, मैं इस सुधार के लिए अपने दोस्त श्री शुक्ल जी को चाहे वे प्रोग्रेसिव हों, प्रगतिशील हों या न भी हों, उन्हें भी बधाई देता हूँ और मिर्धा साहब को भी बधाई देता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं ज्वाइन्ट मिलेक्ट कमेटी के तमाम मेम्बरों को भी बधाई देता हूँ। मुझे आशा है कि मैंने इस सम्बन्ध

में जो मुझाव रखे हैं, उन पर मिर्धा साहब सहानुभूति के साथ विचार करेंगे और जो कुछ धब्बा डेमोक्रेसी पर रह गया है उसको हटाने की कोशिश करेंगे।

इन गब्बों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

SHRI B. T. KEMPARAJ (Mysore) : Mr. Deputy Chairman, Sir, the Select Committee has done its best in amending the Criminal Procedure Code which has been in vogue for the last several years in our country. The Select Committee has been able to reduce the sections in the Code to the extent of 284. One important thing they have done is they have included provisions regarding maintenance in section 125. Regarding other things, they are there with some modifications here and there. No further care has been taken to have any radical changes to suit the present conditions of the society. It is necessary for us to think how all these laws and codes which were imposed on us by the Britishers could be radically changed in order to suit the changing circumstances in the country. Sir, it was these very provisions of the Criminal Procedure Code which Mahatmaji certified in his struggle for independence and after achieving independence should we persist take shelter under the provisions of these laws which were imposed on our country in order to protect the interests of the Britishers? We have to consider how far these things should continue.

At least in my view a beginning has been made to develop a legal procedure, as to how they have to be dealt with hereafterwards. Here I want to refer to section 241 which says:

"If the accused pleads guilty, the Magistrate shall record the plea and may, in his discretion, convict him thereon."

In sections 239 and 240 only an opportunity of being heard is given. It says here:

"... after giving the prosecution and the accused an opportunity of being heard, the Magistrate considers the charge against the accused to be groundless, he shall discharge the accused, and record his reasons for so doing."

[Shri B. T. Kemparaj]

Section 240 says:—

"If, upon such consideration, examination, if any, and hearing, the Magistrate is of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offence triable under this Chapter, which such Magistrate is competent to try and which, in his opinion, could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused."

Then *suo motu* the Magistrate can convict him. Here is a lacuna according to me because it is a very well-known presumption that the accused must be given a chance to prove his guilt beyond all possible doubt. The only accused may be convicted. Here by giving an opportunity to the prosecution and the accused to submit their arguments and, after hearing their arguments, if the Magistrate finds that the accused is guilty, he can straightaway convict him if he pleads guilty. This is a new thing in this Code

"

My suggestion is that this has to be looked into.

Coming to the maintenance clause, a provision has been made, as it was previously in the Code, that the maintenance of minor children, father, mother and the wife, has to be considered by a court of law. The same procedure has been followed here also. There is no serious attempt made to give protection to a person who comes seeking the protection of the court. Only after an offence has been committed the police makes investigations. This is a thing which the Joint Committee ought to have taken into consideration. Unless an offence is committed, no police officer takes cognizance of it and tries to give immediate relief. Therefore, it is necessary, in the case of noncognizable offences, to see that the protection of the police is available to the suffering people. Therefore a way has to be found to give protection to the persons who are put to harassment and trouble and the police describe this offence as a noncognizable offence. Under such circumstances, it is for the authorities to make it possible for giving protection to such persons who cannot get the protection of the police.

According to me the entire Code could have been divided into five Chapters—(1) Preliminary; (2) Powers and duties of the officers who are directly connected with investigation and filing the charge sheet on receipt of the first information report; (3) Trial of cases summarily under summons and warrant and also at Sessions; (4) This Chapter might have included appeals; and (5) Miscellaneous things such as public nuisance, breach of the public peace, maintenance and other things. The Bill which is before us could have been a shorter one so that many of the advocates could go into the various sections very easily and could know the law very well. But this has 484 sections. Advocates, people in the legal profession, have to study this afresh. And it becomes a sort of secondary school for them. If it had been in an abridged form with only those sections which have been amended, it would have been better. Anyhow, we have made a beginning and I think hereafter a Bill may come which may prove equal to the changed environment and conditions of the country.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL (West Bengal) : Sir, firstly I will take the point about custody and refusal of bail. My good friend Nawal Kishorji had touched the fringe of that point but he had not followed it up. To me, as a humble student of law, after the Constitution has been adopted, this taking into custody and refusal of bail is a tyranny which has been described by no less a person than our Rabindranath Tagore as the most reprehensible primitive form of despotism. Sir, remember, on the 15th August, 1947, after the dark hour of midnight, after the zero hour, was over, we were told that we were free from the white rule.

Sir, there was a feeling of freedom before the mind of everybody and this sense of relief was consolidated by the Constitution. Sir, in the Constitution we converted ourselves to a Republic, every citizen becoming a citizen of the Republic, and we gave to ourselves a promise of social equalities, social justice and equality before the eye of law. Sir, with that preamble, which is the most sacred testimony in the Constitution, if you look at the provisions of this Bill, I maintain, Sir, you will find that the whole thing is subversive of the Constitution—it is derogatory to the principles

of social and natural justice; it is detrimental to the dignity of the common man and it is violation of the pledge of equality.

Sir, look at clause 437(1). There it is stated that a man should not be granted bail after the police has arrested and brought him to the court if there are reasonable grounds for believing that they are guilty of certain offences. Sir, at that stage when the law presumes the accused is innocent, the trial is far away, yet, who the devil gives the power to whom, the police or the court, to refuse bail by believing at that stage that that man is guilty of such and such offence. This is ravishment of the principles of the Constitution.

Then come to article 14 of the Constitution. It says:—

“The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.”

Sir, while a person comes to the police, makes a false information or any information and he gets the patronage and the privilege of an adopted child or a domesticated son-in-law of the State and is given all freedom to assemble true evidence and to manufacture false evidence, a citizen who is an accused, who has not to prove to be innocent, is kept in the cold storage of the jail in the corner, not able to assemble his evidence to prove innocence forthwith, not able to bring before the police or the magistrate that he has been falsely prosecuted.

Sir, article 20(2) makes it clear that :

“No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once.”

My lawyer friends are there. And is both disjunctive and conjunctive. If a man is kept in detention, if he is kept in prison, he is punished. So before the trial commences he is awarded punishment and kept in the jail. Is it equivalent to *ad interim* punishment like *ad interim* injunction that we get in civil courts? Make a hell of it

Then, Sir, article 21 says:—

“No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.”

So when these people are kept in jail and bail is refused, actually the legal procedure for trial has not commenced. Sir, the legal procedure come in sessions case in chapter 18. Trial of warrant cases is chapter 19. Trial of summons cases is in chapter 20. Summary trials is in chapter 21. Chapters 23 and 24 are chapters for taking evidence and other miscellaneous proceedings. So, the provisions refusing bail at all these intermediate stages contravene articles 22 and 21. So, as a student of law, I say that clause 437(1) where the provisions have been maintained for refusing bail, is antagonistic to the fundamental rights as adumbrated in articles 22 and 21. Therefore, by virtue of article 13(2), these detention clauses are absolutely *ultra vires* and void.

Sir, I hope in your life you have been accused in political cases. Now, article 22 of the Constitution has given us a guarantee and an advantage.

“No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult, and to be defended by, a legal practitioner of his choice.”

What does it mean? If I am arrested and kept in detention, I cannot have the advantage of having a lawyer of my choice, because what is the choice? You go to the market. You go to this shop or that shop or a third shop before you finally decide what will be your choice in respect of the article you require, and what will be your choice in respect of the price. Therefore, it is ordained by the Constitution that the man must have the freedom to go out to sound lawyers—he may not have gone to senior lawyers at all in his life before that—and then make his choice. That freedom is taken away. Therefore, this detention is *ultra vires* and antagonistic to the Constitution.

My friend, Mr. Nawal Kishore, spoke of trials going on for one year. You know the Shahibari case. Whatever may be the political thinking of parties, as a lawyer

[Shri Sasankasekhar Sanyal]

I say that these hundreds of people are rotting in jail for the last nearly three years. Some of them, Vinay Kumar and Gokul Roy, were returned MLAs at that time. Their names did not appear in the First Information Report. Their names did not appear in the statement before the police for several months. Sir, an European judge would at once ask "Mr. Public Prosecutor, does this man's name appear in the First Information Report?" "No Sir, but there are other evidence". "Don't talk about other evidence. Release him forthwith". But these people are denied bail and the State would stoutly oppose bail from court to court. And this, I repeat, is ravishment of the Constitution.

Coming to article 19, it says :

"All citizens shall have the right—

(d) to move freely throughout the territory of India;

(e) to reside and settle in any part of the territory of India;"

Of course, if he is found guilty, certainly he will be held in prison. But apart from that, this freedom is there. But it is hemmed in by sub-article (5) of article 19. It says:

"Nothing in sub-clauses (d), (e) and (f) of the said clause shall affect the operation of any existing law etc." if that imposes reasonable restrictions either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe.

The *quodam generis* you will find that this does not apply to a person when he has been compelled to be under custody before the trial is commenced. What are the grounds for the detention of a man? So long we have been hearing that certain persons have to be kept in detention for certain reasons. What are they? One is necessary for him to be put in custody for test identification parade. My good friend, I shake hands with him, he has deleted this as the cause of detention. But I can at once tell him as a lawyer with about 50 years of experience that it is the only reasonable and cogent ground for keeping a man in custody at least for some time because in a dacoity case some people may have recognised in the house some unknown

persons. They have to be put under TIP and if they are released on bail, there is no valid identification. But if that is taken out, there are only two other grounds, abscondence and tampering with evidence. Abscondence is a nasty theory. Every person loves his family. Every person loves his society. Every person likes to face a trial, even to go to jail for life for twenty years and come back and have a family life. How many people have absconded? Have you taken statistics? In my career of 50 years I have done several thousands of big criminal cases. In my experience there were only two persons who absconded but they were not recovered. I wanted the West Bengal Government to give me statistics, but they could not furnish. In a history of 50 years there were only a dozen cases. So people love their family. Do you know why people abscond? Not because of fear for trial, for facing trial; they abscond because they know that once they are put under police custody, the kisses of the loving police are too much, if they are put in jail, their life is a hell there. Therefore, in order to keep themselves away from the police and the jail tyranny they abscond. But once you have made it clear just as in civil cases, no defendants will abscond. A person who knows that there is a decree, yet he may be put in a civil jail,—during the trial you don't say to compliment that you must secure the trial—he will back out at any time. Similarly, do you think that a person who loves his family and society will ever go underground and suffer from more terrible agony? This is the theory which does not stand. There again in the trial Vinayakumar and others were denied bail for more than three years. Therefore, several hundred people who were wanted in that unwanted case are in hiding. Even in West Bengal 10,000 people are moving about like vagrants because they do not want to go into the clutches of the police although they know that even in these days, in these days of fast retrograde judiciary, if they appear before a normal judge, they would be acquitted. But they are terribly afraid of the police and their detention in the jail. About the police, the less said, the better it would be the same about the jail. That is why good people are afraid of them. Prisoners are brickbattled, lathi charged and billeted. Now, so far as tampering with evidence is

concerned, when a policeman is accused of murder or a person belonging to the ruling party is accused of murder, he is at once given a dictated bail, and there is no question of tampering with evidence there. When non-conformists are brought in false cases and accused, this condition of tampering with evidence comes in. There are two things involved. Are we supposed to think that our society is so depraved that a wrong doer will be able to influence truthful people to deflect from the path of rectitude? It is a shame. But what about the premium that you are putting upon the prosecution? They are free to manufacture evidence. They are free to terrorise the people and this is in the absence of the accused. If the accused remains free, he can point out to the Police during investigation: "This is the evidence which has proved the falsehood of the prosecution story. Here is the evidence which will prove my innocence. If I am in jail, evidence in my favour can be washed out and evidence against me can be manufactured". Therefore, I maintain, bail should only be used for the purpose of enforcing attendance of the accused and not for purposes of giving him punishment or pig-sticking. You know what is pig-sticking? You beat up a pig with a stick until it is half dead and then you become a hero. When people are moving for bail from court to court, when their resources are exhausted and when the trial actually comes up they have no resources to face the prosecution by engaging good lawyers or by persuading people to give evidence in their favour, this refusal to give bail is denial of justice. When a man loses Rs. 1,000 or a house in decree what does it matter because when you steal my property or money, you commit theft, but when you steal my liberty, you are guilty of rape of the Constitution. A large number of peasants and workers have come into this category. Who will look after them? The State appoints Public Prosecutors for conducting at State cost many false cases. When the accused is put in the cold storage in a corner of the jail, except in 302 cases, no lawyer is engaged to defend him at State cost. Why not? Moreover these lawyers who are selected for defending the accused, have to come from a panel and this panel constitutes lawyers who are either third class or fourth

class. I do not mean any disrespect to them. The first class lawyers, whom these people would have otherwise engaged and whom they cannot engage because their resources are exhausted, are not available to them and therefore they have to accept these colourless lawyers to undertake their defence in serious cases. There is another point also to be considered. Apart from the Constitutional ground, is it natural justice to pour your money over petty and false prosecutions and deny money and assistance to the accused in detention in cases involving even capital punishment or the like? Shri Nawal Kishore said that political rivalry has also to be taken into account. Nowadays cases and cases are being launched by the ruling Party in West Bengal against peasants and workers. . .

SHRI BRAHMANANDA PANDA
(Orissa) What about the UF rule?

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL :
When this Bill is being considered, we have to consider the ruling Party in every State. We have to consider the ruling Party in the Centre also. I might mention that West Bengal is now under absolute, tyrannical Congress rule. U F. Government did not send common man to jail. Therefore, Sir, I am mentioning about these workers and peasants.

Sir, the industrial workers who want to go back, after negotiations, to their factory for work, at the factory gate are arrested and kept behind the prison bars. But, Sir, if by some sort of an accident a man is found guilty of having committed an offence before the police, the police not knowing that he has got his father or his grandfather in the ruling party, arrests him in good faith as an ordinary dutiful policeman should do and the guilty man is taken to the station. Now, Sir, the Minister comes, his in-laws come; and the Minister's hielings come and they dictate to the police that the individual must be given bail. I do not grudge any bail being given to an offending police officer or an offending member of the ruling party. But, Sir, I submit that in order to avoid this discrimination, you should make the grant of bail the rule and refusal of bail the exception. *(Time Bell rings)*
Sir, only a few minutes more. I am glad that you have given me some time.

[Shri Sasankasekhar Sanyal]

If you hand over the whole matter to the police by keeping people in detention, the awe of the police is there and the policeman comes after the murder and he throws the net on the whole village. Sir, the real offender goes away and a whisper is sent to his ears: "Well, you pay something to him. You must satisfy him by paying something to him and you also be a false witness." And, then, Sir, the police people go to the other people in the village and tell each one of them, "Well, you are suspected in this case. People are saying that you are involved in this murder." Now, Sir, these people get frightened. Taking advantage of this, the policemen extort money from these innocent people. This is how the police corruption has been given a premium and refusal of bail leads to such corruption which it is the profession of the ruling party to do away with. But, Sir, in practice, the ruling party wants to perpetuate it in its own interest.

Sir, I now come to the security proceedings. As my friends have mentioned, after all, what is it? Either the Judicial Magistrate or the Executive Magistrate will take action on police reports mostly. Again, Sir, confession before the police is inadmissible in evidence. A statement taken by the police under Section 161 is inadmissible in evidence. Sir, the law distrusts the police, but the Magistrates will have to act upon the reports of the police. Therefore, Sir, I submit that this negation of the bail, the refusal of bail, is inconsistent with the Constitution, is anti-constitutional, is improper, is unfair, is intolerable and is against the principles of natural justice. Thank you, Sir.

MR DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned till 2-00 P.M.

The House then adjourned for lunch at fifty-nine minutes past twelve of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock. MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

श्री भोला पासवान शास्त्री (बिहार) :
उपाध्यक्ष जी, कानून की निगाह में सभी नागरिक बराबर हैं ऐसा हम सुनते आये हैं और आज भी सुन रहे हैं, लेकिन क्या समाजिक दृष्टिकोण में, आर्थिक दृष्टिकोण में, राजनीतिक दृष्टिकोण में, समाज में बराबरी का भाव है? नहीं है। इसलिए मैं इस मिश्रण में कभी विश्वास नहीं करता। जहाँ समाज में इतनी विषमता हो, जहाँ एक गरीब आदमी कानून को खरीद न सकता हो; उस की यह हिम्मत न हो कि जो न्याय है उसे वह अपने पैसे में खरीद सके, उसका इस्तेमाल अपने भले के लिए कर सके, वहाँ इस तरह की बात कहना गलत है। बराबर इस बात की दुहाई दी जाती है कि कानून की निगाह में सभी सिटीजन्स बराबर हैं, लेकिन यह एक खोखली बात है, वेबुनियाद बात है और इस का कोई आधार नहीं है और मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि आज भी इसी बात की दुहाई दी जाती है। जिस कानून पर आज हम लोग बहस कर रहे हैं यह एक सौ साल पुराना हो गया है और अंग्रेजी राज में जो हालत थी वही हालत आज भी है। उसमें कोई अंतर नहीं आया है। इसीलिए मुझे आश्चर्य है कि जब यह अमेडमेंट लाया गया, हालांकि इसमें अच्छे अच्छे मुद्दाव हैं, अच्छे अमेडमेंट्स हैं और दूसरे मित्रों ने दिये हैं और मिनिस्टर साहब ने भी अपने बयान में कहा है कि यह इस सदी का सब से अच्छा कानून है, तो यह सब तो होता रहेगा। यह सब होंगे कानून के अन्दर अमेडमेंट होगा, लेकिन इस कानून को जिसको कि सौ वर्ष में ज्यादा हो गये और जिस रूप में इसका अमेडमेंट आया है, मैं आपसे सच्चाई से कहना हूँ कि इससे पैसे वालों को फायदा हो जाएगा, धनी आदमी को फायदा हो जाएगा लेकिन गरीब को कभी फायदा नहीं होगा।

इस कानून में भी जिसकी मैं उम्मीद करता था कि आज ऐसा कानून आयेगा, स्वराज्य होने के बाद 25 वर्ष के बाद कम से कम गरीब आदमी को, गरीब इंसान को भी कुछ सहायता कोर्ट में मिलेगी। मिलेगा कैसे क्योंकि उसके पास साधन नहीं है। जब समाज में इस तरह की विषमता है तो वह कानून को कैसे खरीद सकता है? वह 302 दफा में फँस जाता है। जो गरीब आदमी पकड़ा जाता है, अरेस्ट होने के बाद ही उसकी आधी मृत्यु हो जाती है। अगर वह गरीब रहा तो 302 दफा में गरीब के केस की सुनवाई नहीं होती है। वह कुसूर नहीं करेगा तो भी उसको फाँसी पड़ेगी क्योंकि वह अच्छा वकील नहीं रख सकता है, वह पालकीवाला को नहीं रख सकता है।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) पालकीवाला तो कस्टीडियन का वकील है।

श्री भोला पासवान शास्त्री हम कस्टीडियन की बात नहीं कर रहे। हम तो पालकीवाला की बात कर रहे हैं। हम तो वह बात कहने के लिए उठे हैं जिसके बारे में हम लोग हैं। इसलिए आज मैं उम्मीद करता था कि जो कानून आज आप ला रहे हैं, इसको आपने बड़ी आसानी से ला दिया, बड़े सीधे तरीके से ला दिया और मेरा ख्याल है कि यह विचार नहीं किया गया कि हमको इंडियन पीनल कोड को बदलकर किस तरह का मौलिक परिवर्तन करना चाहिए। यह तो अंग्रेजी राज्य का बना हुआ है। ठीक है, आपने उसमें कुछ अमेडमेंट ला दिये, मैं यह नहीं कहता हूँ कि आपने खराब काम किया, मेरा इशारा सरकार की तरफ या किसी दूसरे की तरफ नहीं है कि आपने खराब काम किया, लेकिन इन अमेडमेंट्स में गरीब

समाज को, जो पिछड़ा हुआ समाज है, उसको इसाफ मिलने वाला नहीं है, उसको फायदा होने वाला नहीं है जब कि वह स्वतः कानून को खरीद नहीं सकता है। जिसके पास पैसे हैं उसके पास ही अच्छे वकील भी जायेंगे और उसीकी सुनवाई होगी, वह गवाह भी ला सकते हैं। लेकिन गरीब आदमी का कचहरी में इसाफ मिलेगा यह मुझे विश्वास नहीं है। यह बतलाया जाएगा कि जो गरीब क्लास है, गरीब लोग हैं उनके लिए अपने क्या प्रावधान किया? आपने तो मान लिया कि कानून की नज़र में सब पब्लिक बराबर है और आपने आखे मुँद ली। इससे काम चलने वाला नहीं है। इससे समाज का भला हो जाएगा, कोर्ट में उसको फायदा हो जाएगा। यह आपने नहीं मोचा। यह मैं आपको कहूँगा कि आप अमेडमेंट लाये, लेकिन फिर भी वही पुरानी बातें, वही पुरानी रफ्तार, वही पुराना चिन्तन। उसमें कोई भी परिवर्तन, दृष्टिकोण का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब यह है कि उसको लाना चाहिए था, आज आप नहीं लाये हैं तो आपको मोचना चाहिए और आगे लाना चाहिए। कानून की निगाह में सब गिट्टीजन बराबर है, यह धोखा है, महा-धोखा है। मैं इसको कभी नहीं मान सकता। कानून में बराबर है, मगर समाज में बराबर नहीं है। समाज में कोई छोटा है, कोई बड़ा है। कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, समझता नहीं है, कोई जहालत में पड़ा हुआ है। वकील उसकी मदद नहीं करता है। वह कचहरी में माग मारा फिरता है। अगर कानून की यह नज़र रहेगी तो मैं कह देता हूँ कि आप कानून का अमेडमेंट कीजिए। लेकिन जिसको जरूरत है कानून का सहाय मिलने की उसको इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है जब तक की आप कानून में मौलिक परिवर्तन नहीं करते हैं।

[श्री भोला पासवान शास्त्री]

आज भी आप लाये हैं तो इस स्थिति में भी आपको सोचना चाहिए था कि इसमें हम कैसे तथा कुछ कर सकते हैं कि नहीं की गरीब लोगों को कम में कम कुछ फायदा हो। इसका तो फायदा धनी लोगों को होगा। जितना कड़ा कानून है वह गरीब लोगों के लिए है और कानून की जितनी सहूलियत है वह सब धनी वर्ग के लोगों के लिए है। जाहिर है इसमें कुछ भी छिपाने की बात नहीं है। इसमें कुछ बताने की बात नहीं है। यह तो समाज की बात है। जितने हथकड़े पटुचने हैं कानून के गरीबों के यहाँ वह हथकड़े अमीर के यहाँ नहीं पटुचते। अमीर का काम मजिस्ट्रेट साहब भी कर देते हैं, मिनिस्टर साहब भी कर देते हैं, ऊपर से भी कर देगे, उसका काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। लेकिन गरीब का काम जो कुछ जानता नहीं है, मत्तू बाधकर जाता है कोर्ट में, तारीख पर तारीख पड़ती है और उसका घर बैठ जाता है वह कमायेगे तो अपने बच्चों को खिलायेगे या कचहरी में ले जायेगे ? इस दृष्टिकोण से कानून पर आपने विचार नहीं किया। इसमें दोष किसको दिया जाय। सरकारी बेच को कहे या अपने को कहे। किसको कहे इसमें सब के सब दोषी हो सकते हैं। हमने सोचा ही नहीं। जो बना हुआ रहता है, जो लीक है, उसी पर चलना शुरू कर देते हैं और तब तक चलते रहेंगे जब तक कि कोई शक्ति नहीं आवे जोकि उखाड़ कर के फेंक दे। तो हम कहते हैं कि इस दृष्टिकोण को बदलिये और ऐसा विचार रखिये कि कानून के हम लकीर के फकीर नहीं हैं, कानून को हम कोई अपने सिर पर चढ़ा कर नहीं रखेंगे, कानून हमारे सिर पर चढ़ कर नहीं बोलेगा, कानून पर हम कंट्रोल करेंगे। वह

दृष्टि लाइये तभी काम चलेगा। और हमारा विश्वास है कि जो सिस्टम हमारा है, जो हमारा कास्टीडियुशन है जिसके अन्तर्गत हम काम कर रहे हैं, जो सामाजिक स्थिति है और जो पार्लियामेन्टरी सिस्टम है, जिसमें हम काम कर रहे हैं, वह कानून में विश्वास करता है, पार्लियामेन्टरी सिस्टम आफ गवर्नमेंट जो है वह गवर्नमेंट आफ ला है, तो मेरा अटूट विश्वास है कि ला के जरिये से समाज का परिवर्तन हो सकता है बशर्ते कि हम ला के प्रति सिसेयर रहे, ला के प्रति ल्वायल रहे, उसे अमल में लाये और अगर वह अमल में नहीं आता है तो वह समाज-विरोधी काम हो जाता है। अगर कानून इफेक्टिव नहीं है तो इसको बदलने का अधिकार है और इमीलिये पार्लियामेंट है, इसीलिये असेम्बली है कि जिस कानून में समाज का काम नहीं चलेगा उसको बदलेगा लेकिन बदलने का जो प्रासेस है वह उसी तरह है जैसे कि ओ० टी० रेलवे की गति थी कि चल रही है तो चल रही है रुक गई तो रुक गई। हमारे बहुत में दोस्तों ने कहा कि बड़ा अच्छा कानून है, बड़ा बढ़िया है। कौन चीज बढ़िया है। हम तो समझते हैं कि जैसे और कानून बनता है वैसे ही है, खाली अमेडमेंट है, सामान्य ढंग से आर्डिनरी ढंग से जैसे और मामलों में देखा जाता है उसी तरह से इसमें भी देखा गया है। इसमें कोई यह दृष्टिकोण नहीं है कि समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों का विशेषकर के गरीब तबके के लोगों का लाभ हो। अगर ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों का फायदा नहीं है तो उस कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिये। उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है।

श्रीमन् मेरा यह दृष्टिकोण कभी नहीं है और न रहेगा कि सरकारी बेच

वालों को दोष दूंगा किसी को द। मैं तो यह सोचना हूँ कि यह बात चलने वाली नहीं है। आप यह विचार रखिये, मोचिये, कि आज हमारे हाथ में देश की ताकत है, पार्लियामेंट में मेजागिटी है, देश की हुकूमत को चला रहे हैं। अगर हम, हुकूमत, न करे तो कौन करेगा। कौन सोचेगा। सब की नजर हुकूमत के ऊपर रहती है क्योंकि वह रिमोर्फुल है, उसको ताकत है, उसका अधिकार है। तो यह बातें क्यों नहीं सोची जाती है कि ऐसा कानून लावे, ऐसा कानून करे कि जिसमें ज्यादा में ज्यादा आदमियों को फायदा हो और खास कर के गरीब का जरूर फायदा हो। धनी आदमी जो है वह होशियार है, पढ़ा लिखा है, उसकी पहुँच है, उनका काम तो आज भी हो जाता है और आगे भी हो जायगा। हम तो वैसे आदमी के लिये कहते हैं जो कि निसहाय है, जिसका कहीं कोई नहीं है। उसको कचहरी में जाना पड़ता है और न मालूम उसको क्या क्या करना पड़ता है। अब उसको पकड़ कर के दो वर्ष के लिये जेल में रख दिया जाता है, दो वर्ष के बाद वह छूट भी गया, गुनहगार नहीं निकला तो क्या नतीजा है। दो वर्ष उसको रखा। अब उसके बच्चे कैसे खायेंगे, पीयेंगे, कैसे वह जिन्दा रहेंगे। क्या कोई उसको दो वर्ष का कम्पेन्सेशन देते हैं। कोई कोर्ट नहीं देता है। कोई सरकार नहीं देती है। इस तरह का टार्चरस ला, आदमी को तंग करने वाला कानून इस देश में नहीं चलने वाला है और नहीं चलेगा। यह मैं इसलिये सलाह दे रहा हूँ कि आप मोचिये, समझिये। केवल कानून लाने में नहीं होगा। विचारधारा को बदलिये, दृष्टिकोण को बदलिये। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो आप कानून बनाते हैं एक एक आदमी पर उसका

असर पड़ता है। वह कानून जानें या न जानें लेकिन वह कानून के शिकजे में पड़ जाता है। कानून उसको परेशान करता है, पुलिस परेशान करती है, मजिस्ट्रेट परेशान करता है, वह बच नहीं सकता है। हम यह सोचें कि हमको कैसा कानून बनाना है। ऐसा कानून बनाना है जिसमें कि ज्यादा में ज्यादा पब्लिक को, गरीब आदमी को, राहत हो। मैं कोई धनी आदमी के खिलाफ नहीं हूँ वह भी आदमी है, उसे जीने का, रहने का, कमाने खाने का, हक है लेकिन यह नहीं होना चाहिये कि कानून में ही ऐसा क्लज हो जाय, ऐसा कानून बन जाय, जिससे कि धनिक वर्ग फायदा उठाये और सारा का सारा गरीब वर्ग, सारा का सारा समाज, उससे वंचित रहे। इस तरह का दृष्टिकोण हो। आपके पास कैसेज होंगे, आप जानते हैं। हम लोग सब पब्लिक वर्कर हैं, सब के सब कोई धनी नहीं है, कुछ लोग धनी घरों से आते हैं। लेकिन हम गरीब घर से आते हैं।

बहुत आदमी धनी घर से आए हैं, मैं गरीब घर से आया हूँ। हमको जो अनुभव होगा उसके आधार पर कानून में सुधार करने की सलाह देगे। अभी जो किमिनल ला का एमेन्डमेन्ट हो रहा है उसमें हमारा विरोध नहीं है, वह कुछ नए और अच्छे मजेशन्स लेकर आया है, क्योंकि उस पर सोच विचार करने के लिए कई मेम्बर लगे हुए थे। 1970 का कानून है अभी इस साल आया है, बहुत सारे क्लजेज इसमें हैं, बहुत सा सुधार हुआ है। लेकिन मैं कहता हूँ इसमें गरीब के लिए कोई फायदा नहीं। जब हम अपने प्रदेश में काम करने थे तो सोचा करते थे कि क्या करने से सुधार हो सकता है। कहा गया कि स्टेट गवर्मेन्ट को बदलने

[श्री भोला पासवान शास्त्री]

का अधिकार नहीं है, पावर नहीं है, सेन्ट्रल एक्ट है, यह सेन्ट्रल गवर्मेन्ट से बदलना होगा। मझे आशा थी, उम्मीद थी, कि हमारी सरकार इस पूरी चीज को देखेगी और ऐसा एकानून बनाएगी जिसमें गरीब को भी कानून में फायदा होगा, उसको कानून को मानने की भावना हो। कानून अपने देश में बहुत है लेकिन जिस कानून से गरीब पीसा जाता है, मारा जाता है, मक्खी की तरह दुर्गन्ती है, उसमें देश बनेगा या क्या होगा। आप बना लीजिए, जो कानून का फायदा उठाने वाले हैं वे फायदा उठाएंगे। जब कि इस कानून को चलते एक सौ, सवा सौ वर्ष हो गए और स्वराज्य हुए 25 वर्ष हो गए, अब आप बदलने जा रहे हैं, तो कौन सा दृष्टिकोण लेकर बदलने जा रहे हैं। दृष्टिकोण वही पुराना दकियानुसी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण से काम चलने वाला नहीं है, इसको बदलना होगा (समय की घटी) और बदलना चाहिए। अब यह ऐसा नहीं समझिए कि आसान काम हम कर रहे हैं क्योंकि जब वह दबा क्लाम तब समाज में तवाही होगी। उसको हम लोग देखते हैं किस तरह से गरीब आदमी को तबाह किया जाता है कचहरी में। यह कबन हम बनाए हैं तो क्या आगे नहीं तबाह रहेंगे। उन लोगों को क्या पता जो अभिजान कुल में पैदा हुए, जिन्हें चांदी के टुकड़े के दर्शन होते रहे। तो हम जानते हैं, हम राज्य के चीफ मिनिस्टर थे, जब डिफेंशन केस चला दिया पोलिटिकल पार्टीज ने तो किस तरह से हमको खड़ा होना पड़ता था और हजारों आदमियों की भीड़ होती थी। पैसा उनके पास था केस कर दिया। मजिस्ट्रेट और पुलिस के सामने किस तरह हम केम लड़े थे? जब जिदगी में स्ट्रगल ही करना है

तो किसी तरह से लड़े। तभी हम उसकी चोट और पीड़ा को जानने भी है, गरीब जानते हैं। अब जो यहां यह कानून बना रहे हैं तो इस चीज में इमेजिनेशन में काम लेना चाहिए और इस बिल को पास भी करेगा यह हाऊस। तो मेरा तो बोलने वालों में नाम भी नहीं था लेकिन हमने चाहा अपना फंज निबाहू, इस राज्य सभा का, पार्लियामेंट का मेम्बर हू, कम से कम मैं अपना दृष्टिकोण तो रखू और कहीं आगे भी कहीं अमेन्डमेन्ट करना पड़े तो इस लाइन से मोचे आप। जिस चीज के बारे में कहने के लिए खड़ा हुआ वह ऐसा रास्ता नहीं है कि आप उसको दरकिनार करें, नजरबदाज करें और चले जाए या नहीं सोच विचार करें। इसलिए मैं इस विश्वास के साथ इस बिल को सपोर्ट करता हू कि जो अच्छे सजेशन हैं, आगे के लिए मैं कहता हू, जब कभी वक्त आएगा तो उनके ऊपर अमेन्डमेन्ट लाए ताकि उसका लाभ गरीबों के घर में जाए, झोपड़ियों में जाए। एक गरीब को, मजदूर को भी मालूम हो कि गवर्मेन्ट का कानून है। हमारे जो रेप्रजेंटेटिव लोग हैं जिन्हें जनता ने भेजा है, प्रतिनिधि बना कर दिल्ली भेजा है, वे हमारे काम को देख रहे हैं। तो इसको अच्छा कानून बनाओ, इससे दिल में खुशी होगी। इसमें कोई नैरोनेस नहीं हो, बड़े आदमियों के लिए कानून नहीं हो। अगर ऐसा होगा तो समाज का बड़ा में बड़ा आदमी पड़ा रहेगा, वह कानून चलने वाला नहीं है, वह टूटेगा। हम कानून का पालन करने वाले हैं तो हम यह देखें कि इसमें टार्चर न हो। मैं साफ कहता हू जो कानून गरीब के रास्ते में बाधक होता है, जिससे गरीब को फायदा नहीं है, हम उस कानून को नहीं

मानते हैं। वह जुल्म है। इसलिए जब कलाज बाई बलाज विचार चलेगा तो इन बातों पर विचार किया जाए। मेरा तो इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं लेकिन चूंकि ऐसा विषय था इसलिए हम खड़े हुए कि हम पबलिक के रैप्रेजेंटिव्स हैं, हम यहां उनकी तरफ से कहने के लिए आए हैं अतः इस मदन के सामने अपना दृष्टिकोण अर्ज कर दूं आपके सामने। इसके अलावा और कुछ विशेष नहीं कहना है।

SHRI SANAT KUMAR RAHA (West Bengal) : Mr. Deputy Chairman, first of all I would like to congratulate Mr. Shastri and I am in full agreement with the spirit of what he said. I am not a student of law but I was a victim of this Criminal Procedure Code some time back and may also be in future. So I speak from my own bitter experience of life. We are discussing here the Criminal Procedure Code as changed by the Joint Committee. In the spirit of Mr. Shastri I can say that we are discussing old wine in new bottle. Our social system grows out of relations, mainly of productive relations. The main point which Mr. Shastri has placed before this House is this that this House and this Parliament should first improve the situation which has arisen out of the system. Our society in this country is changing because of the productive relations and the system we have is very oppressive and exploiting. It is in this background that we have to discuss the changes to be brought about in the Criminal Procedure Code. I know from my own experience in life that crimes mainly grow out of social contradictions. It is nothing but the result of property relations. So long as we have these vested interests in society we cannot escape from this sort of crimes, moral crimes, social crimes, political crimes and economic crimes which are today dominant in our society. This is the main feature of our society in India today. It is these types of crimes that are going to be handled by this Criminal Procedure Code. How can you handle them? Sir, as crime grows out of the capitalist society as a result of productive relations naturally exploitation

must be there but our Government professes that their aim is socialism, democracy and social justice. I naturally expected that this Bill would help in achieving that aim and would do something towards at least social justice. I do not talk of democracy, I do not talk of socialism but at least to some extent social justice can be upheld by this Government which claims to work for a classless society, a socialist society. But it is a very sad commentary on the work of the Joint Committee that its Report has not come up to the needs of our changing society. This Bill is really important because 25 years after independence we are now going to establish a new order, a new law. The British for their own interests created the Criminal Procedure Code in order to perpetuate their colonial exploitation, in order to perpetuate their police rule through the medium of administrative bureaucratic magistracy. When the Congress Government is loudly talking so much about socialism and democracy I expected that they would give serious consideration to this phenomenon in our society. They should consider carefully how the society is to be run, how the laws should govern, how order is to be set up and how peace is to be established through such laws. Sir, there are some minor changes suggested by the Joint Committee but the vital sections which affect the masses through which the British sought to keep the masses in their grip under police rule, under the rule of their bureaucracy and magistracy, are still very much there. Sections 107, 108, 109, 110, 144 and 151, all these are applied in all cases of social injustice. In the case of trade union workers, kisans, share-croppers, landless labourers, youth and students, immediately any democratic movement, peaceful democratic movement is started, these sections are ruthlessly applied by the police and by the magistrate. So, according to my thinking, all these sections should be deleted. Otherwise, how can we save our society? The majority of the people come under the grip of these oppressive sections. If you wisely consider all these things, I think the Congress rule, whose objective is social justice, cannot be established. Social justice cannot be established without removing these sections. Recently there have been many cases of oppression and excesses by the police. Everyday in the news-

[Shri Sanat Kumar Raha]

papers we read that police excesses are there. Still the Joint Committee has given the police these powers with some minor amendments which have nothing to do with the people. All these things go in favour of the vested class and interests. I think the time has come when we should think a new and there must be some code for police crimes as well as for economic crimes. For police crimes there must be a special code. This Code has nothing in it to solve all these things within our society. So, I think the Criminal Procedure Code, as changed by the Joint Committee, has not kept pace with the growth of our society. Whether you want it or not, our aim is democracy, socialism and social justice. People will not be always satisfied with this Criminal Procedure Code. This Code will be torn up by the people and it will be thrown into the wastepaper basket. This Code cannot help the people in their daily life, in their future prosperity or in their prospects of livelihood.

Another point I raise is this. One of the aims of this Code is to speed up and expedite cases but what has it done? It has failed. Only the scope in some cases has been extended. No major change is there. How can we expedite and have speedier justice and make it successful when our poor people are rotting day and night inside the jail and outside the jail?

Another point I want to raise is about free legal aid. No provision has been made for the down-trodden and poor people who want protection from the police, from the Thana and from the Government. Nothing has been done towards this end. Why? All these are meant consciously for serving the interests of the vested class. All these things are meant consciously for serving the interests of the capitalist-class. They are used against the trade union workers. They are victimised. In the case of Kisans the Jotdars take advantage of the situation. The provision of legal aid has been completely left to the Governments of the States. Why? It is very ugly because you have already crippled all the States financially. The financially-crippled States cannot give financial help to the poor people to defend their cases for getting justice in courts. F.I.Rs., police remand, all these are for the vested interests. It can be manipulated, tam-

pered with according to his wish. "Our masses the poor people think that the police is a terror, they are not the servants of peace; they think that the thana is more terroristic than the prison itself. They think "If I go to the thana, I will be kicked out of the thana because I am a poor man." You cannot protect these people from the tortures and exploitation of the vested class and the police jointly. Even the police alone can do these things. Your apparatus or machinery or administration or your judiciary or your magistrate, all are jointly going against the poor people. So, I think that these things should be seriously considered. Shri Sanval spoke of the so-called appeal and police remand. I am in full agreement with what he said because he has always been my defence lawyer; he has always defended me whenever I had committed any political action.

I request the Minister to consider all these. I am not at all happy about the result, about this Joint Committee's Report on this Criminal Procedure Code. It is a very big, voluminous book. But it has nothing to satisfy the people; it has all to help the vested class, the capitalist class, the land-owning class and others who will always take opportunistic advantage of the present society. Though it has come from the Joint Committee, I cannot fully agree—to commend it. So, with all these serious criticisms, I request the Minister to give serious consideration to my suggestions. It is a Bill on which the rule of the Congress is to be established; law and order would be changed according to the perspective of the ruling party if it is imposed.

SHRI SHYAM LAL YADAV : I would not have taken the time of the House. But there are certain matters which I would like to explain. I appreciate the points made in the speeches of my three friends. We should appreciate that this Criminal Procedure Code has been the basis of jurisprudence in our country since long. And everyone in the country, even a person in the remote village, knows some of the sections and procedures of the Code. Therefore, it would not be possible for any Government to make any revolutionary change nor change the entire structure of the criminal jurisprudence in the country. An attempt has been made in the present Bill to make the provisions

rather easy and to enable the course of justice easy and for a quick decision to be taken so that there may be some justice done in time. There are certain major changes that have been made in the Bill, from the present Code. One of them is that summons cases have been made punishable up to two years instead of one year, and warrant cases have been made punishable over two years. Then the procedure has also been somewhat changed. Powers of the magistrates have been changed. Magistrates of first class used to award sentences only for 2 years. Now, they can award a sentence of three years. He can impose a fine upto a maximum of Rs. 2,000 previously; now, he can impose a fine upto a maximum of Rs. 5,000. In the same way, magistrates of second class can inflict up to six months of imprisonment it has been advanced to one year. The fine was limited to Rs. 500, now it has been raised to Rs. 1,000. And a new magistrate, Chief Judicial Magistrate, has been added here, about which point I will submit later on. He has been given the power to award punishment up to seven years. At present, the Additional Judicial Magistrates are functioning in the different States. They have the power of only the magistrate, first class. Now, the Chief Judicial Magistrate will have the power of the Assistant Sessions Judges and he can award punishment up to seven years. In that way we see that big cases can be tried by Magistrates and the higher courts should not be crowded with many cases which take so much time. The procedure for summons cases has also been made applicable to a large number of cases.

Then, Sir, one thing which has been done through this Bill is the separation of judiciary from the executive. It has for once been done through statute on an all-India basis. Up till now in some States separation has been done by legislation of the State Assembly and in some of the States separation has been done by an executive order of the State Government. But now this Code envisages two types of magistrates. Whenever the word "magistrate" is used in the Bill it refers to judicial magistrate and whenever the word "judicial magistrate" is not referred it is always used for "executive magistrate, and more and more cases withdrawn from the

courts of executive magistrates are handed over for trial to judicial magistrate. I think the people and the bar of the country will appreciate this big step in the separation of judiciary from the executive.

One thing more. The honorary magistrates have been abolished, by and large. But I regret that the Government could not agree to total abolition of honorary magistrates. Only second class special magistrates have been provided. A safeguard has been accepted by the Government on the insistence of the Committee that these second class special magistrates will be appointed by the High Court, and for one year at a time. They cannot be appointed for more than one year. The High Court may enhance the period again by making fresh appointment. So, I think in some ways that objection is met.

There are certain other new provisions which may be appreciated, Sir. For the first time in proceeding under section 107 it has been provided that if the proceeding does not terminate after six months and the opposite party is in custody, the proceeding will automatically drop. If he is on bail then the magistrate, as special reasons, can enhance the period for trial; otherwise the proceeding will terminate. In the Bill there is some obvious drafting omission which I have tried to plug through my amendment on which I would be speaking later.

So far as I remember it was originally agreed in the Committee that clause 116 will provide for stoppage of proceeding after six months. If the magistrate passes an order of continuance of the proceeding for special reasons, that order should be open to revision by the sessions court. In the Bill, as circulated, we find that an appeal is provided. An appeal will be too much because that is almost an interlocutory order. So I have proposed that the order for not stopping the proceeding in a case under section 107 should be tried by the sessions court.

Coming to section 314, I find from the proceeding that it was agreed that if a court while delivering the judgment comes to the conclusion that the witness who appeared before it has made deliberately and willingly false statement he will be

[Shri Shyam Lal Yadav]

prosecuted for perjury in the way prescribed in that clause. But the Bill now mentions that if he has made contradictory statements to his statement made before the police or before the magistrate under sections 161 or 164 he can be charged for perjury. I have proposed an amendment that that portion should be deleted and the decision as taken earlier by the Committee should be accepted and if the person has made a false statement and the court comes to that finding at the time of delivering the judgment that person should be tried for perjury.

Then Sir there is clause 381. Our friend Mr. Syed Ahmed referred to it yesterday. I am in agreement with him that there is some flaw in the drafting. Otherwise, that objection would not have been raised. I have proposed that clause 389(3)(i) should be deleted and in sub-clause (ii) instead of exceeding three years it should be not exceeding three years. That is if a person is convicted by a court and at the time of conviction he is convicted only for a bailable offence then he should be given bail immediately for filing in appeal he will not be sent to jail. But if the case was a warrant case and he was convicted and punished with imprisonment for a period not exceeding three years and he was on bail, then also he will be granted bail and he will not be asked to go to jail pending the appeal. That is the right arrangement and I hope the amendment that I have proposed will be accepted.

Now there is one controversial point in clause 407. It is provided that the accused person or any person has the right to move for transfer if he feels that the court trying is prejudicial to the accused or any person. Once he moves for transfer the provision as it exists today and as is proposed in the Bill also as decided by the Joint Committee unanimously and accepted by the Government is that the Magistrate will stop the proceedings as soon as the accused person brings it to his notice that he wants to make a transfer application for transfer of the case to a higher court. He will no doubt take a bond from him and he will grant only a certain limited period

to enable him to bring a stay order from the higher court. Now the amendment as proposed by the Minister and circulated to us seeks to delete this clause. I had a discussion with him yesterday and some of our friends also had a discussion with him. I told him, 'This is a very stringent proposal that you have made'. I said that because the house will agree that it is in very rare cases that an accused person or his lawyer goes for transfer of a case. It is very rare. Even if the accused wants it there are very few lawyers who will dare to say that the case may be transferred because they have to appear every day before the Magistrate and they cannot incur the displeasure of the court. They will advise their clients not to move for transfer. Only in extreme cases, it is done. The law provides for all types of cases. It is not that the law provides only for general cases. It provides for exceptional cases also. In this case, if the accused person wants to move for transfer and he tells the court, 'I want to move for transfer' then if the court is prejudiced it will proceed and decide the case. The accused person will not be able to do anything. Even if he gets the transfer he will be helpless and he will be sent to jail. So this will cause a lot of hardship. I think the plea advanced on this account is that the cases are usually delayed because of transfers. But from my own experience at the Bar and from the experience of others, I can say that there are very few cases in which transfers are asked for or in which things are delayed. I can visualise cases in which important persons or resourceful persons are involved, even today, in spite of the law, in spite of the amendment that is being proposed by the Minister they can get a stay order from the higher court. They can delay proceedings in the court in so many ways. There is no difficulty for them to get it done. But Sir the poor litigants will suffer. I think the Minister should appreciate the feelings of the Committee and should not go back upon the understanding that he gave to the Committee. He was very kind to accept it in spite of the stubborn opposition from his officials or advisers. I think he should stand by that understanding and accept the Joint Committee's Report on that point. He should not press his amendment.

Lastly, some of my friends have said that the preventive sections should be dropped. We have already amended section 109 to a very large extent, and only one type of case can come up before the court now. So far as the other provisions of the Bill are concerned, I think there has been a significant increase in the facilities provided to the accused persons. For example, in the realisation of fine, Clause 421 provides that if he undergoes imprisonment, fine will not be realised. If an undertrial is undergoing trial and is in detention, and if he is sentenced ultimately, that period of detention will be deducted from his ultimate detention. Now for the first time a limitation has been provided, limitation is undergoing trial and is in detention, and till today there was no limitation. Now anticipatory bail has been provided in Clause 438. And one more bail has been provided. My friend was referring to the case of identification, specifically; that is the usual method that the police bar the bail, the police raise the plea of identification. Now it has been provided that bail will not be refused only because of lack of identification. That is a big advancement. Then, there is a lot of corruption in the verification of bail bonds. That has been provided in this, that verification will be provided by the magistrate or those who are subordinate to him and not by any other extraneous authority like the revenue officials or the police officials, because there is a lot of corruption. The magistrate will verify himself the genuineness or the adequacy of the bond or will depute some other magistrate and will not send the papers to anybody else. That is a good advancement. Then I think the maintenance chapter is good and it has been appreciated by all. Now maintenance is being provided not only to the children, not only to the wife, but to the parents, the indigent parents also. Lastly, I would like to say that the Minister will kindly accept this amendment which I have proposed and withdraw his own amendment.

SHRI BIPINPAL DAS (Assam) : Mr. Deputy Chairman, Sir, the judicial system plays a very important role in a democratic country. We are aiming at bringing about a socialist society, a society based on social justice. We are also committed to the principles of democracy and we are

not going to do it overnight by revolution. We are going to achieve our objective through democratic processes. And therefore, in this process the judicial system is also very important. It must play a significant role. It must help in the advancement of our objectives. It is from that point of view that I would look at this Joint Committee Report. The Joint Committee Report, I must submit, is quite welcome from various points of view. And before I can discuss that question, I would like to take this opportunity of strongly repudiating the allegation made by my esteemed friend, Mr. Sanyal, that the ruling party is using all the various laws only to serve the interests of the ruling party. I strongly repudiate that. I think he was overzealous in trying to condemn the Government on that point . . .

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL : I wanted to give credit to the ruling party.

SHRI BIPINPAL DAS : At the same time I would say that although the Joint Committee has made a substantial improvement over the old legislation, I do not think it has gone far enough. The Joint Committee should have gone still farther. I do not want to go into the details as you have given me only ten minutes. I am only pointing out a few things that strike my mind just now. For example, one of the basic questions that must be answered by all judicial systems is that the common people must be given quick justice. I have seen the various provisions made in the Joint Committee Report. But still I feel that enough has not been done. For example, they have decided to confer some powers on some sub-registrars by way of help to the common people, so that they can get quicker justice. I think they should have gone a little farther. If a magistrate in a town or city is beyond the easy reach of the common people, the people in the villages, I do not think even the sub-registrar is within the easy reach either, not very easy.

Therefore, something should be thought out and a new device or system should be evolved so that the common people, particularly those who live in remote villages, get quick justice.

Where does the judicial process actually start? It does not start in the law court. For all practical purposes it starts with

[Shri Bipinpal Das]

the Police Station—the Thana. First the complaints, charges and counter charges go there and the accused are hauled up and then the cases are brought before the court. Now, what is the conduct of the Police? Can we do something in this regard through legislation and not merely by executive decisions or orders in order to see that the police harassment is stopped? The poor people, the working classes, the peasantry and particularly the Harijans are the worst sufferers at the hands of the Police. They being the first agency to initiate the legal process and if they themselves start harassing the poorer sections of the people, can you call the justice to be meted out to them afterwards, justice in fact or in reality? This is the question I pose before the hon. Minister and the Government.

The Police use all kinds of methods and I know they resort to third degree methods, harassments, torture and all sorts of things. Some statutory provision must be there to stop these things. Any Policeman who resorts to any of these things should be punished and punished drastically. For that there should be some legal provision. All of us know that these things are going on. But what have we done to stop these things?

Then, what about anti-social elements? I am very glad that some provisions have been made, in regard to hoarders, profiteers and those who violate laws on foreign exchange. There are provisions here, but the ultimate question is what is going to happen in practice. Even now there are some laws against hoarders, profiteers, black-marketeers and so on. But what is going to happen in practice.

SHRI GOLAP BARBORA (Assam): Especially under Congress rule.

SHRI BIPINPAL DAS: I do not know what will happen when his party comes to power. We have seen enough of these opposition parties. They cannot claim to have the monopoly of all the honesty and integrity in the world. Every major opposition party in this country has been tested in one part or other of this country and every one of the opposition parties has been found wanting. Therefore, do not blame Congress alone. Be a little responsible. This is a common job . . .

AN HON. MEMBER: That is the consolation.

SHRI BIPINPAL DAS: This is no consolation. This is a pointer to the fact that the disease has gone very deep in the society. We have to root out the disease. We have to do it along with all others. There is no question of one party or the other party doing it. I know what the opposition parties are. I was in the opposition for long years. Please do not provoke me. . .

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: On a point of order. He says I cannot provoke him. Why not he evoke the best in me?

SHRI BIPINPAL DAS: That we will do in the lobby, outside.

I was saying about anti-social elements. On some minor technical grounds, many of these people escape punishment. I agree that the Joint Committee has tried to do something about it. But this is not sufficient. We have to do something more in order to see that they do not escape from the clutches of law.

What about delayed procedure? Shri Yadavji has mentioned clause 107 and said that the proceedings must be completed within six months.

Under special circumstances it may be extended. Leave alone the question of extension. I would like to ask Mr. Yadav and any lawyer-Member present here and also every Member of this House: "Is six months not a very long time for proceedings to be drawn up against a person who is already in custody?" You say that this period of six months can also be extended. . .

SHRI SHYAM LAL YADAV: It is not for persons in custody. For them it should be terminated within six months.

SHRI BIPINPAL DAS: My question is this: "Even if you keep it as six months, is it not too long a period?"

SHRI SHYAM LAL YADAV: Yes.

SHRI BIPINPAL DAS: Do you think that justice is done by detaining a person for six months and you delay drawing up

the proceedings against him? Why should there be a delay? If there is a case, if there is a concrete case, why should there be any delay in drawing up the proceedings against him?

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: I have given you instances where people have been kept for three years without trial.

SHRI BIPINPAL DAS: Therefore, Sir, I feel that something should have been done on this point also. My question is how to improve the efficiency of the functioning of the entire judicial system. This is the basic question and today, Sir, in this country it is just not there.

Then, Sir, about over-crowding in jails by undertrials. Again, Sir, the Joint Committee has said quite a lot about it and tried to do something about it. But why should it happen? Why should there be at all any over-crowding in jails by undertrials? This issue of under-trials has become so nauseating for me, absolutely nauseating. A man can be there for a few days, for a week or two and the proceedings should be drawn up against him and if he is guilty he should be punished; otherwise, he should be let off.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: The word "undertrial" has not been defined in any law.

SHRI BIPINPAL DAS: Sir, these are the few points which I wanted to make because I personally feel very much about these. I welcome this Report. Although I say that this Committee tried its best to improve upon the old Code, I do not feel entirely happy about it because a little more remains to be done.

Then, Sir, I come to certain general questions. Some time back, Sir, if I remember aright, the honourable Law Minister, Shri Gokhale, assured us—I do not know whether here or there, whether in this House or the other House—that something will be done to help the poor by way of legal aid. Just remember, Sir, that 22 crores of our people are living below the subsistence level. If one of them wants to seek justice and if he has to go through

all these procedures and proceedings, what will happen to him? He has not enough money even to feed his family, not enough money to have two meals a day and if he has to go through all these procedures and proceedings, what will happen to him and what are you going to do about it?

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: Sir, may I enlighten him a bit on this? In the meetings of the Joint Committee on the Advocates Bill, a clause came up for discussion relating to legal aid to the poor and the expectation was that a chapter would be introduced in the Bill. But the Committee has dropped it.

SHRI BIPINPAL DAS: Mr. Sanyal, at the age of seventy or above seventy, you try to behave like a young man of twenty-five.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: I am still young. I feel young.

SHRI BIPINPAL DAS: I am very glad about it and I congratulate you on your energy. Please do not interrupt me thinking that I am contradicting you.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: You also do not envy me for my energy.

SHRI BIPINPAL DAS: I envy your energy.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: I feel flattered.

SHRI BIPINPAL DAS: Now, Sir, the basic question I pose before the House and the Government is this: "What are we going to do to help the poorer sections of our society to get justice quickly and easily and cheaply?" This is the basic question which we should tackle if we really mean any business by socialism and all that. Probably we may progress a little slowly. I also know that in a democratic set-up we cannot do things overnight and so we have to make progress slowly. But you must do something about this. What have we done so far? And, Sir, what are we going to do now? This is what I want to ask now.

[Shri Bipinpal Das]

In this connection, I want to say something and I hope my lawyer friends like Mr. Sanval and Mr. Yadav will pardon me if I say a word about the fees taken by the lawyers from the poor people in this country.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: We are for that.

SHRI BIPINPAL DAS: What is happening today? Are you doing justice to yourselves? I address the entire lawyer class in this country. Are they doing justice to themselves, to the people of 3 P.M. this country or to the cause which they hold dear in this country? I do not want to make any more comment on this. Let them think for themselves. Some of them show their love of social justice, socialism, equality and so on. And they shed tears for the poor people of this country. But what is going on in law courts? How can you reform the system? Let the lawyers of this country, I appeal to them, come forward themselves and fix a limit . . .

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: On a point of order. Does he know that lawyers are supposed to act without any remuneration? Does he know further that an eminent lawyer does at least 50 per cent of his work free of any remuneration?

SHRI BIPINPAL DAS: I know many of them. I am not going into that . . .

SHRI H. S. NARASIMH (Mysore): Mr. Palkhiwala donates Rs. 5,000 per day for charitable purposes.

SHRI BIPINPAL DAS: I am not going into individual cases. I do not say that there are no good men among lawyers. I do not say that. I am talking of the lawyers as a class, in general. They must act and assert. Everybody knows what is happening in this country. I appeal to them to reform this. . .

SHRI B. T. KEMPARAJ: As far as the advocates are concerned, it is not the correct view.

SHRI BIPINPAL DAS: I know. I know many of my friends who are practising law. . .

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: Let my friend be prosecuted and I shall defend him free of charge.

(Interruptions)

SHRI BIPINPAL DAS: My lawyer friends get upset when I say this. What is the truth? I plead with them, I appeal to them, to come forward themselves. They have well organised Bar Councils, Associations and so on. Let them come forward and do some justice to the poor people of this country by fixing a limit to their fees.

Last point, Sir, I did not want to say, but I just mention it. I know that there is corruption in this country in various branches, various sectors, various sections. It is no use blaming only one section. But still something should be done. Some efforts should be made at least to rid the judicial system of this evil or at least to bring down the level of corruption in judicial system to the minimum, and to do justice to the poor people if we are to utilize this system ultimately for bringing about a new society based on equality and social justice.

श्री गोलाप बरबोरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई वकील नहीं हूँ, लेकिन पिछले 25 साल के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में कानून, पुलिस और वकीलों के मामले आने का मुझे मौका मिला है और मैं ने देखा है और मेरा यह तजुर्बा है कि देश में जो कानून होता है वह उस देश की समाज व्यवस्था का प्रतीक होता है। मुझे इस कांग्रेसी राज की जेल में भी रहने का मौका मिला है। आज हमारे देश में कानून का एक जंगल बना हुआ है और कानून का डम्नेमाल मंत्री ढंग से न होने का जो एक तरीका चल रहा है उस से साबित होता है कि हमारा नाग भले ही समाजवाद को स्थापित करने का हो, लेकिन हमारा देश पूँजीवाद और सामन्तवाद की ओर ही बढ़ रहा है। क्योंकि हम देखने हैं कि कहने को तो बोला जाता है कि कानून के सामने सब लोग बराबर हैं लेकिन वास्तव में बात यह है कि कानून की नजर में कुछ लोग ज्यादा बढ़े हैं और

उस कानून के सामने उन को ही ज्यादा बराबरी मिलती है। जिला कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आने के लिए जिन के पास 25, 50 हजार रुपया नहीं है उस के लिए कानून के सामने सब को बराबरी हो, इस का कोई मवाल ही नहीं है। आप के कानून की किताबों में कुछ ऐसी धाराएँ हैं जैसे 107 है, 109 है, और मैं जेलों में गया हूँ वहाँ रहा हूँ और मैं ने देखा है कि अडर ट्रायल्स वहाँ रहते हैं।

हमारा जेल शहर का जेल है। कभी उसमें 125 की कैपैसिटी रही, आज 1500 लोग वहाँ रखे जाते हैं। ज्यादातर 70-80 फीमदी अडर-ट्रायल है, अडर-ट्रायल में आसाम की जेलों में रह चुके हैं। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं शिवसागर की जेल में रहा, वहाँ देखा की एक चाय बागान का गरीब मजदूर, हमारे घर में 3 मील दूर चाय बागान में काम करता था, एक दिन अपने रिश्तेदारों के पास गया था। रास्ते में कोई स्टेशन में उतरा। स्टेशन में पुलिस रहती है, उसने पकड़ा कि क्या है पाकेट में दो, नहीं तो जाओ 109 धारा, 107 धारा के अन्दर। पड़ा है जेल में। पैसे वाले लोग तो बराबर जमानत में चले आते हैं, लेकिन गरीब मजदूर, किसान, भूमिहीन जो हैं उनको जमानत में लाने के लिए लोग 20-25 रुपये खर्च करने के लिए तैयार नहीं हैं और वह पड़ा हुआ है जेल में। यह हालत है। जिस देश में 10 करोड़ आदमी बेकार हों उसमें आप 109 में किसी को गिरफ्तार करते हों "for having no ostentious means of livelihood" बेकारों के लिए क्या ऐश्वर्य है? आप उनको लाइवलीहुड का मीन्स नहीं दे पाते हैं तो उसको गिरफ्तार करेंगे धारा 109 में उसको जेल में रखेंगे? उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोर्ट में कोई कागजात दाखिल करने का रास्ता नहीं। इसलिए

हमने यह माग की है, सामाजिक आन्दोलन में हम लोग लगातार यह माग करते रहे हैं कि 107, 109 कानून की किताबों में हटाये जायें। अडर ट्रायल रहता है। एक दफा देखा कि जोर हाट की जेल में 15 साल का स्टुडेंट मर्डर केस में इम्प्लीकेट कर के गिरफ्तार किया गया था और 3 साल तक जेल में रहा। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तब तक चार्जशीट नहीं आई और 3 साल लगातार चलने के बाद चार्जशीट नहीं आई तो उन लोगों ने भूख हड़ताल की कि हमारे खिलाफ किल्यरक्ट चार्ज शीट लाई जाए, हमको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। उनको भूख हड़ताल करनी पड़ी। कोई 70 फीमदी अडर ट्रायल जेल में थे। क्या गुजरती है उनकी जिन्दगी में आप लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, काग्रेसी आन्दोलन में जेल गये हैं उनको मायद मालूम होगा, नये लोगों को तो मालूम होगा नहीं। अडर ट्रायल्स को खाना कम मिलता है। अडर ट्रायल्स को जेल का ड्रेस नहीं मिलता है, वह फटे हाल रहता है। उनकी देखभाल करने वाला नहीं है, वदन में कपड़ा नहीं है, बीमार है, यह हालत है। तो देश में कानून का जगल ज्यादा बढ़ाकर कोई फायदा नहीं है।

हमारा राजनीतिक उद्देश्य अगर समाजवाद का है तो समाजवाद में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो प्रोटेक्शन देने का उद्देश्य है उसी उद्देश्य में कानून बनने चाहिए और ज्यादातर कानून का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यह व्यवस्था अगर हो तो बहुत फायदा देश के गरीब लोगों को मिलेगा। उसके लिए पहला कदम है कि 107, 109 को जल्दी खत्म किया जाए। कम से कम आज अगर हिन्दुस्तान में कहीं 20 लाख लोग जेलों में हैं तो उनमें से 10 लाख लोग जल्दी में जल्दी रिहा हो जाएंगे और सरकार और देश के गरीब

[श्री गोलाप बरबोग]

लोगों का लाखों लाख रुपये की जो बरबादी होती है वह भी बरबादी रहेगी।

श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल (बिहार) : श्रीमन्, मुझे भी बोलना है।

श्री उप-सभापति : आपने कहा था कि आप नहीं बोलना चाहते हैं।

श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल : किमने कहा? अगर यह कहा तो आपको गलत कहा गया। हमने कहा था कि हम पीछे बोलेंगे। दूसरे दिन जायगा तो दूसरे दिन बोलेंगे, यह कहा।

श्री उप-सभापति : हमसे कहा गया कि यह बिल कल तक जायगा तो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। अच्छा आप बोलिये पांच मिनट।

श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल : श्रीमन्, यह बात सही है कि मैं आज ही आया हूँ और मैंने इसको पढ़ा नहीं है इसलिए पढ़ कर के जितना कहना चाहिए, उतना मैं नहीं कह सकता हूँ लेकिन एक बात तो प्रत्यक्ष है कि जो आज हालत देश की है उसमें अगर सब से बड़ा कानून तोड़ने वाला कोई है तो यहां की सरकार है। इसको अगर आपको देखना हो तो जेल में चले जाइये। भागलपुर सेन्ट्रल जेल की कैपेसिटी कितनी है। 1500 है। और कैदी कितने हैं—3000। इस कानून को किमने तोड़ा। सरकार ने तोड़ा। क्या इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में या जो पीनल कोड का मंशोधन आ रहा है उसमें कोई ऐसा प्राविजन है जिस प्राविजन के जरिये कानून को तोड़ने वाला अगर सरकार है, सरकारी आदमी है, तो उसके ऊपर मुकदमा चले। इस तरह का कोई प्राविजन आपने इंडियन पीनल कोड में या इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में किया है। नहीं किया है।

इसलिए जो असली यहां की बीमारी है वह बीमारी यह है कि आज की सरकार जो वर्तमान व्यवस्था है, उस व्यवस्था

को बदलना दिल में नहीं चाहती है, हालांकि मुह में या कानून के रूप में भी वह इस ढंग की बात कर रही है जिससे कि मालूम पड़ता है कि वह ऐसा कर रही है और लोगों को इसमें उम्मीद बंधती है कि शायद सरकार समाज को कुछ बदलना चाहती है। जो हमारा संविधान है उस संविधान के शुरू में कह दिया गया है कि किस तरह का समाज बनाने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए लेकिन जिस तरह के समाज की कल्पना की गई है वैसा क्या बन रहा है। उसके प्रिन्सिपल में जिन बातों का जिक्र किया गया है, जिस इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रट-निटी, डिगनिटी आदि का उसमें वर्णन किया गया है उस बात को क्या अपने सामने रखा है और जो प्लान आपने बनाये है उन प्लान को अगर देखा जाय तो क्या उन बातों को वह रिकलेक्ट करता है। क्या यह बात सही नहीं है कि इसी दिल्ली शहर में और पटना शहर में जो कि मेरे राज्य की राजधानी है वहां पर नई नई बस्तियां बसाई गई और बसाई जा रही है, कहीं पर श्रीकृष्ण नगर है, श्रीकृष्ण पुरी है, कहीं पर किदवई पुरी है, न मालूम कितनी पुरियां हैं लेकिन उन पुरियों को कैसे बसाया गया है। वहां पर गरीब लोगों की बस्ती थी। इनकी स्कीम जो है वह स्लम क्लीयरेंस की है और स्लम क्लीयरेंस के जरिये से सारी जमीन को एक्वायर कर लिया जाता है, ऐसा नहीं होता है कि उस जमीन पर बसे हुए गरीबों को रुपया दे कर उनके घरों को ही अच्छा बना दें, यह स्लम क्लीयरेंस की स्कीम नहीं है। इनकी स्कीम है कि उनकी जमीन को ले लो, मारी बस्ती को उजाड़ दो, उसको साफ मुथरा करो उसमें हर अमेनिटीज को दो और फिर उस पर अपने भाई-बन्धु को जा कर बसा दो। यही इनकी स्लम क्लीयरेंस स्कीम है। इसलिए हम कहते

है कि जो सविधान की मशा है, जो उसके प्रिएम्बल में दिया गया है उसके मुताबिक जो हिन्दुस्तान में प्लान चल रहा है वह क्या चल रहा है इसे देखें। वह प्लान भी उसके मुताबिक नहीं चल रहा है। जो सरकार को चलाने वाले आदमी हैं अगर वह सविधान के मुताबिक कानून नहीं बनाते हैं, प्लान नहीं बनाते हैं क्या वह मुजरिम नहीं हैं, क्या उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाना चाहिए, उनके ऊपर भी मुकदमा चलना चाहिए। क्या इस तरह का कोई सशोधन आप अपने इंडियन पीनल कोड या इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ला रहे हैं कि वह बात हो सके। वैसे कोई बात इसमें नहीं है। इसलिये अभी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इस हाउस के सामने है इससे कोई बड़ी बात होने वाली नहीं है। बराबर यह कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट में बहुत मुकदमे जमा हो गये हैं, लोअर कोर्ट्स में बहुत मुकदमे जमा हो गये हैं और ये सब मुकदमे जल्दी खत्म होना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि मुकदमे खत्म होना चाहिए, जल्दी खत्म होना चाहिए लेकिन एक बात का कफ्युजन लोगों में, बोलने वालों में, रहता है और शायद उस बात पर उनका ध्यान नहीं गया है और वह बात देरी के बारे में यह है कि कभी कभी गरीब लोगों को मुकदमा लड़ने के लिए देरी करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि वह घर जाता है, उसको पैसों के लिए, दो-चार रुपए के लिए वहाँ पर इंतजाम करना पड़ता है, तब मोहलत देता है। तो इस ढंग से अगर कोई देरी न करे तो मुकदमा लड़ भी नहीं सकता है। यह भी एक आस्पेक्ट है देरी होने का। इसलिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अगर इस तरह का प्राविजन रहे कि जो जेनुइन गरीब है, गरीबी की बिना पर वह टाइम चाहता है, तो उसको मिलना चाहिए लेकिन आज वह टाइम मिलता है कहीं किमी को। जिनके

पास रुपया है वह टाइम ले कर हैगस करता है। दूसरी पार्टी अगर गरीब है तो वह न्याय पा ही नहीं सकती है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, इस आस्पेक्ट को भी सरकार को सामने रखना चाहिए।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ वह यह है कि जितना भी आज कानून बनता है, हर कानून में एक प्राविजन किया जाता है कि सरकार के वही लोग जो इस कानून के आपरेशन में लगे हुए हैं, उन लोगों के ऊपर कोई जिम्मेदारी अपने काम की नहीं आएगी, सरकार की कोई लाएबिलिटी नहीं होगी—क्या ऐसा कानून समाजवाद को लाने वाला कानून होगा? क्या इसीसे वह समाज बनेगा जिस समाज की कल्पना काम्स्टीट्यूशन के प्रिएम्बल में की गई है? इस बात का भी खयाल रखिए कि इस तरह से आज जो काम सरकार की ओर से चला है, हाफ हार्टेड वे से चल रहा है, इम्प्लिमिटी उसमें है, मृत्यु का अंश नहीं है। इसलिए आपको अपने काम में मकसम नहीं मिल रही है। अगर आपको यही करना था तो ग्राम पंचायत बनी हुई है, फुल आथॉरिटी दें दे उसको काम करने की। फुल निगरानी करने के लिए जज को पावर कर दें कि जिस ग्राम पंचायत में बेइसाफी हो वहाँ जो इसाफ करने वाला आदमी है उस पर मुकदमा चला दें। इस तरह का प्राविजन करने तो हम मजदूने गरीब के साथ इसाफ है और उसमें सरकार का भी खर्चा बचता, देरी भी कम होती, और जो पंचायत का पंच हो उसको भी डर लगा रहे कि हमारे ऊपर भी देखने वाला आदमी है इसलिए न्यायपूर्वक काम करना चाहिए और उसके ऊपर अपील करने की जरूरत पड़ती, तो हाईकोर्ट में जाकर अपील की व्यवस्था हो सकती।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : Sir, I have very carefully heard the various Members who have taken part in this debate which is on the Bill before us. Many ideas have been discussed and some of the changes that we have made in this Bill from the existing situation have been commended. Well, Sir, there are some aspects of this Bill which I mentioned in my opening speech and I would not like to repeat them. What we have tried to do in this Bill is that investigation and trial of cases should be expeditious and fair, that due protection should be given to the right of the accused and that there should be a check on the arbitrary exercise of power by police and other authorities. Well Sir, a lot has been said regarding the security provisions of the Code and the way in which they are misused. In the similar way, mention has also been made about the provisions regarding preventive arrests by the police. Sir, it seems that there is a deep distress against the whole police as is evident from the speeches made by hon. Members.

It may be true that there are instances when the powers given to the police under the Code have been abused but to condemn the whole police force would be most unfair. After all, the policemen about whom so much is said are part of the society to which we all belong. Most of the police force is from poorer classes of our society and to say that all of them abuse the powers or exceed the powers that are given to them would be not only a gross exaggeration but most unfair to a force which has exhibited on occasions some commendable traits of bravery and fair-mindedness. If we continue this spirit of distrust I think we would be impeding the process which I am sure we all want to initiate of improving the morale, quality and efficiency of the police force. More and more educated people are coming into the police, the officer cadres are selected after very intensive screening and competitive tests and I am sure a definite improvement in their working and behaviour is noticeable which should receive, however grudgingly, at least practical recognition at the hands of hon. Members.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL. Are you grudging?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : I mentioned about security proceedings. If hon. Members would see the changes that we have made some of the criticisms would have been avoided. For example, proceedings under sections 108, 109 and 110 which formerly used to be with the Executive Magistrates now would be handled by the Judicial Magistrates. As regards separation of executive and judiciary also, we have made this separation. It is one of the accepted principles of our legal system. We have given it a statutory basis on a uniform pattern all over the country. Up till now there was separation of the executive and judiciary but the pattern differed from State to State. Sometimes it had a legal basis, sometimes it was merely through executive instructions but in this new Bill we have tried to give it a uniform pattern all over the country and I think it should be welcomed by everyone. We have taken out cases from the Executive Magistrates and given them over to the Judicial Magistrates who are under the High Courts and who can be expected to be very fair and impartial in their outlook and at whose hands none need have any fear about being victimised or being put to any disadvantage.

श्री बीरेन्द्र कुमार सखलेचा (मध्य प्रदेश) :
आपने 108 और 109 को तो ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन 107 के बारे में क्या हुआ ?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : This point was also very seriously debated in the Joint Committee and their decision was that in view of the circumstances under which section 107 is resorted to it would be better if it is kept with the Executive Magistrates because very quick action is needed in cases of this nature where a breach of peace is apprehended. So to put it in the hands of the Judicial Magistrates may to some extent even defeat the purpose for which that section is designed.

SHRI MAHAVIR TIAGI (Uttar Pradesh) : Bail will be available in that case.

AN HON. MEMBER : It is a bailable offence.

श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा : अनभव तो यह है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हमेशा दूर पर और दूसरे कामों पर लगा रहता है .

SHRI RAM NIWAS MIRDHA Sir, a lot of suggestions have been made which really do not form a part, which cannot form a part of this Bill. Just now the hon. Member said that executive Magistrates are not in the court. This is the type of thing which we can not provide for in the Code. It is an administrative matter. I do hope the State Governments are from time to time seized of the matter and they would do what could be done to increase the number of Magistrates to handle these cases. This is something which this Code cannot rectify. This is a type of short coming which will have to be dealt with administratively. Similarly, some suggestion was made that the Station House Officer who does not register an FIR should be punished. This is also something which cannot be provided for in the Code. We have provided some safeguards regarding the filing of first information reports which is the basis for starting any investigation. One of my amendments will make it more stringent. If a Station House Officer does not register an FIR, we are giving the right to the complainant to write a letter to the Superintendent of Police. It would be taken cognizance of and the case could start. Similarly, a suggestion was made by Nawal Kishoreji that the investigating branch and the general duty branch of the police should be separated. That, again, is an administrative reform and I am glad to inform the House that some States have already adopted it. In some of the big metropolitan towns they have a set-up which is exclusively devoted to the investigation of cases and another set-up which concerns itself with traffic and general duties. I hope the States will take more and more steps in that direction, so that we can have less of delay in the investigation and disposal of cases, so that the cases could be investigated in a very thorough manner and delays could be avoided.

" ,

Well, Sir, a lot was said about legal aid. The present system of law does put a poor man at a disadvantage. I am not opposed to that statement as a general

proposition, because the system under which we work does put poor people at a disadvantage. We were conscious of this fact and one important innovation that we have made in this Bill is about legal aid. In all cases which are triable by a court of sessions, the accused person will have the right to be defended by a lawyer at Government's expense and this is quite an advance from the present situation.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: Would it be a lawyer of his choice?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: Well, Sir, there would be rules. The High Court would make rules as to how and in what manner it should be done.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: The Constitution says so.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If the Constitution says so, it is all right. It will take care of it.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: Not only that. There was a feeling in the Joint Committee that we should go even farther than this but since going farther than this would have meant imposing great financial burden on the State Governments it was thought better not to go in for that without consulting the various State Governments because all these provisions would be implemented by the State Governments. They will have to pay for the lawyers who provide legal aid to these accused persons. We have made an enabling provision saying that if the State Governments so desire, whenever they are in a position to extend it, they can extend this free legal aid to the accused in other types of cases. I think this provision would also be used by some State Governments to extend the scope of legal aid.

Well, Sir, some hon. Members quoted the old sections about people without any ostensible means of subsistence being held up and detained. All these provisions have been removed. We were conscious of these provisions and the iniquity of those provisions, without using a stronger word than this. We have removed this provision: "any person who has no ostensible means of subsistence and who cannot give a satisfactory account of himself." It was a section which could be abused and was abused in many cases. We have removed that. Not only that. We have tried to bring in

[Shri Ram Niwas Mirdha.]

the anti-social elements, people who resort to what we can call white-collar crimes against society. We have tried to bring them within the ambit of this Bill.

Provision has been made for demanding security from habitual black-marketeers, defaulters in payment of provident fund dues and other anti-social persons of that nature.

SHRI GOLAP BARBORA: There should be one more provision that at least no citizen should be called to the thana without clear summons. Please make that provision.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: Well, Sir, briefly I have tried to comment upon the various suggestions. A lot of suggestions have come. Some amendments have also been referred to. On most of them I will comment when we come to them. Some of them I might accept. One amendment I am going to bring forward, regarding the automatic stay of proceedings when a transfer application is made. We discussed this in the Joint Committee. And it is an agreed recommendation from the Joint Committee in the sense that no minute of dissent is there about it. As you know and as the House knows, there is no voting by majority or minority in the Joint Committee. That is the tradition of which we are always aware. In the Joint Committee all these measures were thoroughly discussed and even though proposals differed sometimes radically from the proposals that the Government originally formulated, we tried to accept them in the spirit in which they were advanced, which means, to improve the working of the criminal law system in the country. To this particular amendment I will come when it is taken up; and it has been brought forward because the Law Commission have very strongly recommended on it and they have given various reasons; not only this Law Commission but other Commissions before also have said that this provision is many times abused. The process in the court, the trial in the court, is delayed not only by months but years in many cases. And other arguments also I will adduce when I come to the amendments themselves.

With these words, I once again thank the hon. Members.

श्री नवल किशोर: व्हाट एबाउट दिस क्लाज 320 इस मे एक अमेडमेंट की बात थी जिस को आप ने कहा था कि हम एग्री करते हैं और वह शायद मिस हो गया है। उस मे 'दि परसन आर हिज रिप्रेजेंटेटिव' होना चाहिए था। उस को भी राइट आफ कंपाउंडिंग हो, यह बात थी।

श्री राम निवास मिर्धा: उस पर भी बहस की गयी थी और कई तरह के विचार थे कि उस के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को यह हक दिया जाय या न दिया जाय। एक व्यक्ति के खिलाफ कोई जुर्म जरूर होना है लेकिन वह समाज के विरोध मे भी एक जुर्म कहा जा सकता है। इस लिए उस सारे विचार के बाद यह तय किया गया कि उस को न किया जाय और इसी लिए वह अमेडमेंट सेलेक्ट कमेटी ने स्वीकार नहीं किया।

श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस मे हिस्सा लिया है और अपने विचार व्यक्त किये हैं, उन के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करना हूँ और खास तौर मे जो हमारे सहयोगी थे इस सेलेक्ट कमेटी मे, उन के प्रति मैं अपना आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही बुद्धिमानी मे और बहुत ही मेहनत मे इस सारे विधेयक पर विचार विमर्श किया। मेरा विश्वास है कि कमेटी मे जो विधेयक आया है उस मे कई ऐसी बातें हैं जो हमारे प्रशासन को और हमारे क्रिमिनल सिस्टम को सुधारेगी। आज के जमाने के अनुरूप हम ने इस को बनाने की कोशिश की है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to consolidate and amend the law relating to Criminal Procedure, as reported by the Joint Committee of the Houses, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let us now take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 5 was added to the Bill.

Clause 6—Classes of Criminal Courts.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: Sir, I move—

“That at page 28, line 20, after the words ‘first class’ the words ‘and in any metropolitan area, Metropolitan Magistrates’ be inserted.”

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is—

“That clause 6, as amended, stand part of the Bill.”

The question was put and the motion was adopted.

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

Clauses 7 to 25 were added to the Bill.

Clause 26—Courts by which offences are triable.

SHRI NAWAL KISHORE: Sir, I move

25. “That at page 28, after line 44, the following be inserted namely:—

“Illustration.—A is committed to the Sessions Court on a charge of culpable homicide. He may be convicted of voluntarily causing hurt—an offence triable by a Magistrate.”

The question was proposed.

SHRI NAWAL KISHORE: Sir, it is a very innocent amendment and is just an illustration. It was just to explain the thing. But if Mr. Mirdha does not accept it I will not press it. I beg to withdraw it.

Amendment No. 25 was, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:—

“That clause 26 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 26 was added to the Bill.

Clauses 27 and 28 were added to the Bill.

Clause 29—Sentence which Magistrate may pass.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: Sir, I move:—

2. “That at page 29, after line 31, the following be inserted namely:—

“(4) The court of a Chief Metropolitan Magistrate shall have the powers of the court of a Chief Judicial Magistrate and that of a Metropolitan Magistrate, the powers of a Judicial Magistrate of the first class.”

This is more or less a formal thing by way of clarification and I hope it will be accepted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is—

2. “That at page 29, after line 31, the following be inserted, namely:—

“(4) The court of a Chief Metropolitan Magistrate shall have the powers of the court of a Chief Judicial Magistrate and that of a Metropolitan Magistrate, the powers of a Judicial Magistrate of the first class.”

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:—

That clause 29, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 29, as amended, was added to the Bill.

Clauses 30 to 34 were added to the Bill.

Clause 45—Protection of members of the Armed Forces from arrest

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : Sir, I move:

3. "That at page 35, lines 2—3, the words 'and of clause (d) of sub-section (1) of section 196' be deleted "

The question was proposed.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : This is a small drafting amendment and I hope it will be accepted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN. The question is:

3. "That at page 35, lines 2—3, the words 'and of clause (d) of sub-section (1) of section 196' be deleted "

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN. The question is:

That Clause 45 as amended, stand part of the Bill

The motion was adopted.

Clause 45, as amended was added to the Bill.

Clauses 46 to 77 were added to the Bill

Clause 78—Warrant forwarded for execution outside jurisdiction.

SHRI NAWAL KISHORE: Sir, I move:

26. That at page 41—

(i) in lines 4-5, for the words 'any Executive Magistrate or District Superintendent of Police or Commissioner of Police' the words 'Chief Judicial Magistrate or Chief Metropolitan Magistrate' be substituted; and

(ii) in lines 6-7, for the words 'Executive Magistrate or District Superintendent or Commissioner' the words 'Chief Judicial Magistrate or Chief Metropolitan Magistrate' be substituted."

The question was put and the motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That clause 78 stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clause 78 was added to the Bill

Clauses 79 to 82 were added to the Bill.

Clause 83 (Attachment of property of person absconding)

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL : Sir, I move.

13 That at page 42, line 32, after the words 'at any time' the words 'but not within thirty days' be inserted "

The question was proposed

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL : Sir I only want to bring parity. I want the period of 30 days given to attachment to be given to the proclamation also.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : Sir, this amendment is not acceptable because it will defeat the very purpose of attachment. If 30 days' notice is to be given, then every property will be disposed of and there will be nothing to attach.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

13 "That at page 42, line 32 after the words 'at any time' the words 'but not within thirty days' be inserted "

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That clause 83 stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clause 83 was added to the Bill

Clauses 84 to 115 were added to the Bill

Clause 116 (Inquiry as to truth of information)

SHRI SHYAM LAL YADAV : Sir, I move :

30 "That at page 54, after line 11 the following be inserted namely:—

(7) Where any direction is made under sub-section (6) permitting the continuance of proceedings, the Ses-

sions Judge may, on an application made to him by the aggrieved party, vacate such direction if he is satisfied that it was not based on any special reason or was perverse.' "

The question was proposed.

SHRI SHYAM LAL YADAV : Sir, I have already spoken about it. The Government will kindly accept it. They have agreed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Are you accepting it?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : Yes

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

90. "That at page 54 after line 44 the following be inserted namely:—

'(7) Where any direction is made under sub-section (6) permitting the continuance of proceedings, the Sessions Judge may, on an application made to him by the aggrieved party, vacate such direction if he is satisfied that it was not based on any special reason or was perverse.' "

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That clause 116, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clause 116, as amended was added to the Bill.

Clauses 117 to 124 were added to the Bill.

Clause 125.—(Order for maintenance of wives, children and parents) —

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL : Sir, I move.

14. "That at page 58—

(i) line 11, for the words 'his wife, unable to maintain herself,' the words 'his or her spouse, unable to maintain himself or herself,' be substituted.

(ii) line 12, after the word 'his' the words 'or her' be inserted.

(iii) line 14, after the word 'his' the words 'or her' be inserted.

(iv) line 18 after the word 'his' the words 'or her' be inserted."

The question was proposed.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL : Sir, the reason for this amendment is simple. In the days gone by when we married, our wives were a burden and the burden is still continuing. Nowadays in the modern set-up of societies, wives earn not only as much as the husbands in many cases, but sometimes even more. Therefore, just as it is the duty of the husband who has the means to maintain a wife who has no means, similarly it is the duty of the wife to maintain an incompetent husband if he has no means. It is the principle of natural justice. So far as the children are concerned they are as much children of the father as they are of the mother. So why should not the mother who has got means also be liable to maintain the children? It is avoiding discrimination which is very unfair. And it is ethically sound and it is also legally acceptable. I hope this will be done.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : This is a very laudable idea. It was very seriously discussed in the Joint Committee which ultimately came to the decision that the husband for the time being need not claim maintenance from the wife.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The question is—

14. "That at page 58,—

(i) line 11, for the words 'his wife, unable to maintain herself,' the words 'his or her spouse, unable to maintain himself or herself,' be substituted.

(ii) line 12, after the word 'his' the words 'or her' be inserted.

(iii) line 14, after the word 'his' the words 'or her' be inserted.

(iv) line 18, after the word 'his' the words 'or her' be inserted."

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The question is:

That Clause 125 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 125 was added to the Bill.

Clause 126—Procedure

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL : Sir, I move :

15. "That at page 59,—

(i) line 36, for the word 'husband' the word 'spouse' be substituted; and

(ii) line 39, for the word 'husband' the word 'spouse' be substituted."

The question was put and the motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The question is—

"That Clause 126 stand part of the Bill "

The motion was adopted.

Clause 126 was added to the Bill.

Clauses 127 and 123 were added to the Bill.

Clause 129—Dispersal of Assembly by use of Civil Force

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL : Sir, I move:—

17. "That at page 60,—

(i) line 38, for the word 'Executive' the word 'Judicial' be substituted.

(ii) lines 38 to 40, the words 'or officer-in-charge of a police station or, in the absence of such officer-in-charge any police officer, not below the rank of a sub-inspector,' be deleted.

(iii) line 46, for the word 'Executive' the word 'Judicial' be substituted."

18. "That at page 61, line 1, the words 'or police officer referred to in sub-section (1),' be deleted."

The questions were proposed

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL : Sir, after the separation of the judiciary and the executive, the judiciary stands on a respected pedestal, and the executive not so much. And all relevant powers have been taken away from the executive so that the judiciary can do justice even-handed without fear or without any expectation of favour. But the executive is so much involved in political leanings and political predilections that no responsibility as enunciated in this section should be given to them. And similarly, the police, which is also a wing of the executive and polluted from all points of view, should not be given any status. Therefore, I have moved these amendments so that the whole thing may be left in the hands of the judiciary.

श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा : यह क्लॉज 129 में जो अन्लाफुल असेम्बली को डिस्पर्स करने का पावर दिया गया है, एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया—यहां तक तो समझ में आता है कि आप मजिस्ट्रेट्स को यह पावर दे कर किसी असेम्बली को अन्लाफुल डिकलेयर करें, डिस्पर्स करने का आदेश दें लेकिन यह जो दिया है कि—

"or, in the absence of such officer in-charge, any police officer, not below the rank of a sub-inspector, "

यानी, ईवन् एस० एच० ओ० से नीचे किसी भी सब इंस्पेक्टर को किसी असेम्बली को अन्लाफुल डिकलेयर करने का, उसको डिस्पर्स करने का आर्डर दें, इसमें मेरा निवेदन है कि यह बहुत ज्यादा अधिकार देना होगा। आज तक यह पावर मजिस्ट्रेट्स को दिया है (Interruption) लेकिन— even a sub-inspector who is not even in-charge of a station house— यानी कोई नया सब इंस्पेक्टर अप्पॉइन्ट हुआ है तो वह भी किसी असेम्बली को कहे कि अन्लाफुल असेम्बली है, तो उसके लिए मेरा निवेदन है कांस्टीट्यूशन में प्रीएम्बल का जो राइट है फंडामेंटल राइट का, उसको एब्रिज करने की पावर

मजिस्ट्रेट को है जिमको लीगल नालेज है, कमिडरेशन है, वह कह सकता है असेम्बली अन्कास्टिट्यूशनल है लेकिन एक सब इन्स्पेक्टर जो कल ट्रेनिंग लेकर आया है, जिसको इतना एक्सपीरियेन्स नहीं है, वह कैसे कह सकेगा अन्लाफुल है। वह सब इन्स्पेक्टर एक असेम्बल को डिस्पर्स करने का आर्डर दे, इस तरह का जो अधिकार आप उसको देने जा रहे हैं, यह बिल्कुल अनुचित है। लोगो को असेम्बल होने का जो राइट है, उसको अन्लाफुल डिक्लेयर करने का राइट आप एक छोटे से पुलिस के आफिसर को दे रहे हैं, जो मैं समझता हूँ एक ठीक बात नहीं है।

हम लोग इस बात को देखते हैं कि देश में जगह जगह पर उसे असेम्बलीज को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा अन्लाफुल डिक्लेयर किया जाता है और अब इस पावर को इतने नीचे के अधिकारी को देना, सब इन्स्पेक्टर को देना, मेरे विचार में जनता के अधिकारों पर अतिक्रमण करने के समान है। जब कभी मजिस्ट्रेट द्वारा इस तरह के आर्डर किये जाते हैं उनके सम्बन्ध में भी सरकार को ज्यूडिशियल इन्क्वायरी करनी पड़ती है। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि एक सब इन्स्पेक्टर को इस तरह के अधिकार देना उचित नहीं होगा और एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से भी आप इस पर विचार करने की कृपा करें।

SHRI RAM NIWAZ MIRDHA : The first amendment is regarding dispersal of unlawful assembly and so is the other one. These amendments suggest that this power should be given to the Judicial Magistrate instead of Executive Magistrate. The whole scheme in the Bill is that certain powers of an emergent nature be better left to the Executive Magistrates to handle. I think these powers should rest with them, and to bring in Judicial Magistrates at this stage would really defeat the purpose for which provision is meant.

As regards powers to disperse an unlawful assembly to 'any Executive Magistrate or officer in charge of a police station or, in the absence of such officer in-charge, any police officer, not below the rank of a sub-inspector', I would like to say that this power was already with the officer in charge of a police station. The only addition is "or, in the absence of such officer in charge, any police officer, not below the rank of a sub-inspector". The idea is that if there is any immediate necessity to disperse an 'unlawful assembly and if the officer in charge of the police station is not there at that time, then, to quote the language of the Bill, he can "command the assembly to disperse". We are not giving any new power to him . . .

SHRI V. K. SAKHLECHA : You are not giving this power to the Station House Officer, but to an ordinary sub-inspector of police.

SHRI M. P. SHUKLA : What would be the position when the Station House Officer is not in the Station, and the station is raided by a mob?

SHRI V. K. SAKHLECHA : In such a situation, I will readily concede that But Clause 129 does not say that at all.

SHRI RAM NIWAZ MIRDHA : This was discussed in the Committee before they decided to add these words.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The question is .

17. "That at page 60,—

(i) line 38, for the word 'Executive' the word 'Judicial' be substituted;

(ii) lines 38 to 40, the words 'for officer in-charge of a police station or, in the absence of such officer in-charge any police officer, not below the rank of a sub-inspector,' be deleted,

(iii) line 40, for the word 'Executive' the word 'Judicial' be substituted."

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN . The question is :

18. "That at page 61, line 1, the words or police officer referred to in sub-section (1) be deleted."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

That clause 129 stand part of the Bill.

The motion was negatived.

Clause 129 was added to the Bill

Clauses 130 to 153 were added to the Bill.

Clause 154—Information in cognizable cases

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : Sir, I move:

4. "That at page 70, after line 36, the following be inserted namely:—

"(3) Any person aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of a police station to record the information referred to in sub-section (1) may send the substance of such information, in writing or by post, to the Superintendent of Police concerned who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself and direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him, in the manner provided by this Code, and such officer shall have all the powers of an officer in charge of the police station in relation to that offence."

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That Clause 154, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 154, as amended, was added to the Bill.

SHRI V. K. SAKHLECHA : Sir, I wanted to speak on Clause 154. This is the most important part of the Code.

जिसमें एफ आई आर लाज की जाती है। मंत्री महोदय ने जो एमेंडमेंट मूव किया है उसको हम सपोर्ट करते हैं।

AN HON. MEMBER : It is over now.

श्री बीरेन्द्र कुमार सखलेचा : लेकिन कुछ और बातें हैं जिनके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You speak on the Third Reading if you want.

Now it is over.

Clauses 155 to 160 were to the Bill.

Clause 161—Examination of witnesses by police

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL : Sir, I beg to move:

19. "That at page 72, after line 38, the following be inserted, namely:—

"(4) The police officer shall send such written statements to the Judicial Magistrate holding jurisdiction over the matter within twentyfour hours."

The question was proposed.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL : Sir, I hope the honourable Minister will give some attention to what I say. Now, Sir, in a particular case the police goes to the locality. He contacts the possible witnesses. Sometimes he does not contact the witnesses. Sometimes he takes notes on a white paper as to what has been stated and sometimes he does not take even such notes. Long after he writes down the statements of witnesses person by person and in these statements the witnesses are made to say which they have not said earlier, because no signature is needed and no attestation is needed and it is not obligatory that these statements should be recorded in writing in the presence of the village people. Actually, such things should be sent to the Thana forthwith without any delay. Recently, Sir, the Supreme Court has held that even from a distance of 14 miles, if the FIR made under Section 161 does not come in time, within 24 hours, the statements which are supposed to have been made by the witnesses should not be accepted. Therefore, Sir, in order to protect the people, in order to protect the accused from the whims of the police who write anything

they like, who prepare any statement which was not made by the witnesses, this should be done. When the accused goes to the Sessions Court, the Public Prosecutor says, "You said this", and the accused or the witness says, "I never said this" and at that time, unless he sticks to his statement written down by the police, he will be confronted before the judge and he will be harassed by the police. Therefore, Sir, in order to secure the safety of the citizen, it has to be made obligatory that as soon as the statement is recorded, just as the FIR should reach the destination within 24 hours, the statement from day to day should be despatched so as to reach the subdivisional Magistrate within 24 hours. It may be extended if there are any special reasons.

Sir, I think this is very reasonable and in the interest of the people who are accused it is necessary and essential.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Yes, Mr. Sakhlecha you wanted to speak.

SHRI V. K. SAKHLECHA : Sir, I support this amendment on a different ground.

जैसा कि श्री सान्याल ने कहा है, लोगों को इसमें शक होगा क्योंकि केस डायरी के स्टेटमेंट्स के आधार पर उनसे कास एग्जामिनेशन किया जाता है, उनको कोर्ट में कन्ट्रिडिक्शन के परपज के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन मेरा निवेदन यह है पुलिस कई केसेज में और मर्डर केसेज के अन्दर जहाँ पर जरा सा डाउट कोर्ट के माइन्ड में क्रिएट कर दिया तो एक्विटल मिल जाता है, ऐसे केमेज में जहाँ पुलिस को इन्टरेस्ट हो जाता है तो केस डायरी में उल्टा-सीधा बयान लिख कर उस केस को स्पाइल करते हैं। आज उन्होंने ठीक स्टेटमेंट रिकार्ड कर दिए, बाद में भ्रष्टाचार के कारण पुलिस आफीसर का उसमें इन्टरेस्ट डेवलप हो गया तो उसको हटवा कर केस डायरी में बयान बदल देते हैं। और यह बदल देने के कारण एक्ज्यूज्ड का कोर्ट में एक्विटल हो जाता है। इस

नाते एफ० आई० आर० की कापी मैजिस्ट्रेट को भेजना आवश्यक है। इसी प्रकार केस डायरी के स्टेटमेंट, जिस रोज वे रेकार्ड हो उसी रोज भेज दिये जाये तो पुलिस की एवीडेस प्रोटेक्टेड रहेगी और किसी स्टेटमेंट को चेज कर देना या केस में किसी स्टेज पर इटरपोल्यूशन करना और ऐसा कर के उसे स्पायल कर देना इस की गुंजायश पुलिस के पास नहीं रह जाएगी। और इस तरह के चार्जज पुलिस पर अक्सर लगते हैं कि उन्होंने केस में इटरपोल्यूशन किया है। तो ऐसा होने पर उस की इवीडेंशियरी वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी और वह सारी चीज मैजिस्ट्रेट की कस्टेडी में रहेगी और इसलिए पुलिस पर कोई इस तरह का चार्ज नहीं लगाया जा सकता कि सब-इस्पेक्टर ने इस में कोई चेज कर दिया है। इट इज टु दि हेल्प आफ पुलिस ऐंड एडमिनिस्ट्रेशन आलसो। तो इस लिए मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें। ऐसा होने पर जिस प्रकार एफ० आई० आर० की सैक्टिटी है वैसी ही इन की भी हो जाएगी और दिस बिल हैब सम इवीडेंशियल वैल्यू। केस डायरी पर हस्ताक्षर के बारे में यहाँ काफी विचार हुआ है और वही सैक्टिटी अगर आप इस को देना चाहते हैं तो इस की कापी भी आप मैजिस्ट्रेट को भिजवाइये। इस से उस की सैक्टिटी ज्यादा होगी और आप को प्रासिक्यूशन में और कन्विकशन प्राप्त करने में ज्यादा लाभ होगा।

श्री ए० एन० मुल्ला (उत्तर प्रदेश) : इस सवाल पर बहुत गौर किया गया था कमेटी में और जो सवाल उधर से माननीय सदस्य ने उठाया है उस की हिफाजत के लिए पुलिस रुल्स देखे गये थे और बहुत में पुलिस रुल्स और रेगुलेशन जो हैं उन में यह दफा मौजूद है कि यह चीजे जो वह चाहते हैं उन को

[श्री एन० एल० मुल्ला]

फोरन भेजा जाय और बराबर मुकदमा मे यह बहस की जाती है। और अगर फोरन केस डायरी नही जाती है तो कहा जाता है कि इस को बदला गया है और अदालत बराबर इस बारे मे गौर करती है। तो इस की हिफाजत के लिए पुलिस रूल्स और रेगुलेशन मे काफी चीजें मौजूद है।

SHRI V. K. SAKHLECHA : No. You go to any place, and you won't find it . . .

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL : Nowhere.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : It is not proper that the First Information Report and the statement recorded under this clause should be compared, because the F.I.R. is of very great importance in the whole case, whereas the purpose for which the police statements are used is of a very limited nature. They are never used to corroborate the prosecution. They are only used for contradicting a witness in cross-examination. The two things are completely different. In many cases, to introduce a clause like this will make the whole thing very rigid. Sometimes investigations are carried on, which are very far away from the magistrate. There are no facilities for taking copies. The investigating officer has to be there on the spot. As Shri Mullaji has said, these things can be provided in the Police Rules. To provide them in the Code would not be proper.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL : Sir, . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You had your say.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL : We want Division.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

19. "That at page 72, after line 38, the following be inserted, namely:—

'(4) The police officer shall send such written statements to the Judicial Magistrate holding jurisdiction over the matter within twenty-four hours.' "

The House divided.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Ayes—11, Noes—53.

AYES—11

Banarsi Das, Shri

Barbora, Shri Golap

Gowda Shri U. K. Lakshmana

Mathew Kunan, Dr. K

Menon, Shri K. P. Subramania

Nawal Kishore, Shri

Patel, Shri D. K.

Raha, Shri Sanat Kumar

Safar, Shri Ram

Sakhlecha, Shri V. K.

Sanyal, Shri Sasankasekhar

NOES—53

Abid, Shri Qasim Ali

Ahmad, Shri Syed

Alva, Shri Joachim

Anif Shri Mohammed Usman

Berwa, Shri Jamna Lal

Bhaidwaj, Shri Jagan Nath

Bhagohain, Shri Nabin Chandri

Chaudhari, Shri N. P.

Chettri, Shri K. B.

Choudhury, Shri M. M.

Das, Shri Balram

Dikshit, Shri Umashankar

Gadgil, Shri Vithal

Hathi, Shri Jaisukhlal

Himmat Singh, Shri

Hussain, Shri Syed

Kalania, Shri I. K.

Kalyan Chand, Shri

Kapur, Shri Yashpal

Kemparaj, Shri B. T.

Khan, Shri Maqsood Ali

Kollur, Shri M. L.

Krishan Kant, Shri

Kulkarni, Shri A. G.

Kulkarni, Shri B. T.

Lakshmi Kumar, Shri Chandra, Shrimati

Mehta, Shri Om
 Mirdha, Shri Ram Niwas
 Mukherjee, Shri Kali
 Mukherjee, Shri Pranab Kumar
 Mulla, Shri A. N.
 Munda, Shri B. R.
 Narasiah, Shri H. S.
 Naravani Devi Manaklal Verma, Shrimati
 Nurul Hasan, Prof. S.
 Panda, Shri Brahmananda
 Patil, Shri G. R.
 Patil, Shri P. S.
 Puri, Shri D. D.
 Reddy, Shri K. V. Raghunatha
 Roshan Lal, Shri
 Savita Behen, Shrimati
 Shashtri, Shri Bhola Paswan
 Shukla, Shri M. P.
 Singh, Shri Bindeshwari Prasad
 Sita Devi, Shrimati
 Sushila Shankar Adivarekar, Shrimati
 Tiwari, Shri Shankarlal
 Tiwari, Pt. Bhawaniprasad
 Venigalla Satyanarayana, Shri
 Vidvawati Chaturvedi, Shrimati
 Vyas, Dr. M. R.
 Yadav, Shri Shivam Lal

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That clause 161 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 161 was added to the Bill.

Clauses 162 to 171 were added to the Bill.

Clause 172 (Diary of Proceedings in investigation)

SHRI NAWAL KISHORE : Sir, I move

31. "That at page 77, line 32, after the word 'investigation' the words 'and

the said diary shall be despatched next day to the Magistrate having jurisdiction to try the case under investigation' be inserted."

32. "That at page 77, for lines 33 to 42, the following be substituted, namely:—

"(2) The police diaries may be used by the Court to aid it in inquiry or trial of the case concerned and the parties can also make use of them."

The question was proposed.

श्री नवल किशोर : श्रीमन्, वह क्लॉज 172 जो है यह डायरी आफ प्रोसीडींग्स से संबंधित है। इन्वेस्टिगेशंस के अन्दर जब कोई पुलिस आफिसर इन्वेस्टिगेट करके केस डायरी भरता है तो उसमें लिखता है कि उसने कौन कौन से केसेज में, सफतीश कौन कौन से गवाह आये, आदि बातें लिखता है। मैं यह चाहता हूँ कि इसके आखीर में यह भी लिख दिया जाए— "and the said diary shall be despatched next day to the Magistrate having jurisdiction to try the case under investigation".

मेरी मंशा यह है जब डायरी कंप्लीट हो जाए तो दूसरे दिन उसको वहां भेज दिया जाए ताकि डायरी के साथ टेम्परिंग करने की कोई गुजायश नहीं रह जाए।

दूसरा मेरा अमेंडमेंट है। सब-क्लॉज (2) को मैंने इसी में इनकारपोरेट कर दिया है। सब-क्लॉज (3) में लिखा हुआ है कि जो ऐक्यूज्ड है उसको केस डायरी की कापी नहीं मिलेगी। मैं जानना चाहता हूँ कि अब आप दोनों को ऐक्यूज्ड और उसके एजेंट को सुविधा देना चाहते हैं तो जो केस डायरी है यह उन दोनों को अवैलेबल होनी चाहिए, उसको और उसके वकील को मैं समझता हूँ कि अगर मिर्चा साहब ने यह तय नहीं किया है कि कोई अच्छी बात नहीं मानेंगे तो इस अमेंडमेंट को उन्हें मान लेना चाहिए।

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, पहले अमेंडमेंट के बारे में मैं पिछले संशोधन में उत्तर दे चुका हूँ कि जो डायरी है उसकी नकल मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाए, यह किस वजह से स्वीकार नहीं हुआ।

दूसरा संशोधन जो है उसके विषय में मेरा निवेदन है कि पुलिस डायरी का एक विशेष महत्व रहा है और इस संशोधन से अदालतों में भी उसका उपयोग कर सकें या जो पार्टियाँ हैं वे भी उसका उपयोग कर सकें। मैं समझता हूँ कि इससे काफी दिक्कत होगी और इससे हम नयी चीज शुरू करेंगे जिसका प्रभाव आगे चलकर क्या होगा, मैं नहीं कह सकता। इसलिए मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Are you presenting it?

SHRI NAWAL KISHORE : No, Sir.

The amendments (No. 31 and 32) were by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That clause 172 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 172 was added to the Bill.

Clauses 173 to 195 were added to the Bill.

Clause 196—Prosecution for offences Against the State

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : Sir, I move :

5. "That at page 85, lines 28 to 31 be deleted."

The Questions were proposed.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : Sir, this is a procedural amendment. This clause is being taken to the next clause.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That at page 85, lines 28 to 31 be deleted."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

That clause 196, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 196, as amended, was added to the Bill

Clause 197—Prosecution of Judges

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : Sir, I move :

6. "That at page 86,—

(i) the existing sub-clauses (2) be renumbered as sub-clause (4) thereof;

(ii) before sub-clause (4) as so renumbered the following sub-clauses (2) and (3) be inserted, namely:—

(2) No court shall take cognizance of any offence alleged to have been committed by any member of the Armed Forces of the Union while acting, or purporting to act in the discharge of his official duty, except with the previous sanction of the Central Government

(3) The State Government may, by notification, direct that the provisions of sub-clause (2) shall apply to such class or category of the members of the force charged with the maintenance of public order as may be specific therein, and thereupon the provisions of that sub-section will apply as if for the expression "Central Government" occurring therein the expression "State Government" were substituted."

The question was proposed.

SHRI V. K. SAKHLECHA : I want to oppose this.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह धारा 197 में ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो मंत्री जी अमेंडमेंट लाये हैं उसके लिए मेरा यह निवेदन है कि इस अमेंडमेंट का जो पार्ट (3) है उसमें यह है :

"The State Government may, by notification, direct that the provisions of sub-clause (2) shall apply to such class or category of the members of the force charged with the maintenance of public order as may be specified therein, wherever they may be serving, and thereupon the provisions of that subsection will apply as if for the expression "Central Government" occurring therein the expression "State Government" were substituted."

श्रीमन्, मैं सभा भवन का ध्यान धारा 197 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह धारा वह है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट, कोई अधिकारी, अपनी पावर को मिस्यूज करे तो इसलिए कि आफिशियल कपेसिटी में वह काम कर रहा है इसके अन्तर्गत उसको प्रोटेक्शन दिया गया है उसका प्राजीक्युशन करने के खिलाफ और इस कारण से, इस प्राविजन के अन्तर्गत न मालूम कितने घृणित कार्य किये जाते हैं अधिकारियों के द्वारा और फिर भी उनका प्राजीक्युशन नहीं हो पाता है। जैसे कि सब-इंस्पेक्टर्स होते हैं वह थाने के अन्दर बुला कर के मुल्जिमां में मार-पीट करने हैं, उनको भयंकर रूप से यातनायें देते हैं और फिर जनता के आदमी के लिए जिसको कि पीटा गया है, जिसको इंजरीज पहुंचाई गई है, उसके लिए कोई एविडेंस कलेक्ट करना मुश्किल होता है और मुकदमा करना तो और भी मुश्किल होता है लेकिन अगर वह इसके लिए प्रयत्न भी करता है तो कहा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लाइये उसका प्राजीक्युशन करने के लिए और हम जानते हैं कि वह पर-

मिशन उसको जल्दी मिलती नहीं है, महीनों इसमें निकल जाते हैं तभी कहीं किसी केस में मिलती है। सब सदस्यों को इसका अनुभव होगा कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसे कितने मामलों के अन्दर प्राजीक्युशन की इजाजत देती है। यह आप जानते हैं कि सबइंस्पेक्टर्स और पुलिस आफिसर्स अपनी पावर्स का दुरु-प्रयोग करते हैं और इसलिए कि वह पब्लिक सर्वेंट है अनेक प्रकार के अत्याचार जनता के ऊपर करते हैं और जो इस प्रकार का काम करते हैं उनके खिलाफ कोई प्राजीक्युशन नहीं ला पाते हैं। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि सारे पुलिस आफिसर्स को बदनाम नहीं करना चाहिए, कोई अच्छे आफिसर्स हैं, ईमानदार आफिसर्स हैं, काम करने वाले हैं लेकिन जो पावर का दुरुप्रयोग करते हैं पुलिस अधिकारी उनके लिए क्या कर सकते हैं। उनके पास उनका डंडा है, फोर्स है, उनको स्टेट ने यह अधिकार दिया है कि अपनी पावर्स को यूज करे लेकिन वह उसको निरीह लोगों के खिलाफ उपयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में भी अगर वह निरीह जनता, अत्याचार से पीड़ित लोग यह चाहते हैं कि कोर्ट्स में जा कर के उनके खिलाफ कार्यवाही कर सके तो उसके इस अधिकार के ऊपर भी प्रतिबन्ध लगाने वाला यह सेक्शन 197 है। इस नाते से मेरा निवेदन है कि जहां तक जजेज का सवाल है यदि जजेज अपनी ड्यूटी के अन्दर कोई काम करें तो उनको प्रोटेक्शन दिया जाय लेकिन पुलिस आफिसर के बारे में भी ऐसा ही करिये यह ठीक नहीं है। फिर यहां मंत्री जी जो अमेंडमेंट लाये हैं उसमें तो एक कदम और आगे रखा है और कहा है कि यह स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि कौन से पुलिस के इम्प्लाय को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं यह भी इस सेक्शन में डिफाइन नहीं किया है, यह भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़

[Shri V. K. Sakhlecha]

रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट जिन आफिसर्स के बारे में डिक्लेयर कर दे उन आफिसर्स के बारे में बिना परमिशन के प्राजीक्यूशन नहीं किया जा सकता है और उनके लिये सेक्शन 197 का सारा प्रोटेक्शन दिया जाएगा चाहे वह आफिशियल कोपेसिटी को जान कर के कितना भी घृणित कार्य क्यों न करे। तो मेरा यह निवेदन है, मैं यह चाहता हूँ कि अगर वह अत्याचार करे, अपनी पावर को एब्यूज करे तो जनता को अधिकार देना चाहिए कि न्यायालय के अन्दर उनको प्राजीक्यूट कर सके। जनता तो उन्हें दंडित नहीं करेगी, कोर्ट ही दंडित करेगी लेकिन कम से कम जनता कोर्ट में जा कर उनको प्राजीक्यूट तो कर सके, यह अधिकार जरूर जनता को दिया जाना चाहिए। और इस नाते से इसके ऊपर यह रेस्ट्रिक्शन लगाना अनुचित होगा और पुलिस फोर्स के लिए भी ठीक होगा कि सारी पुलिस फोर्स चंद आफिसरों के कारण बदनाम न हो। वह अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और उसके कारण पूरी पुलिस फोर्स की बदनामी होती है। जो वास्तव में दोषी है उनको दंडित किया जा सके इतना अधिक प्रोटेक्शन दोषी अधिकारियों को नहीं देना चाहिए। इसलिए मैं इस अमेन्डमेंट का घोर विरोध करता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट को कतई यह पावर नहीं देना चाहिए, छोटे पुलिस आफिसर को नहीं देना चाहिए। जहाँ तक जज और मजिस्ट्रेट का पावर देने का सवाल है, उनको प्रोटेक्शन देने की बात समझ में आ सकती है।

SHRI RAM NIWAS MIRDHA Sir this amendment is merely of a drafting nature As I said, in connection with clause 196, we deleted certain provision which is now being sought to be transferred to clause 197 The terms of the amendment are just the same as in clause 45 which we have already passed

श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा : क्लॉज 196 वाला नहीं है। वह तो आम्बे फोर्मेज के बारे में है।

श्री राम निवास मिर्धा : यह आम्बे फोर्सेज के बारे में है। दरअसल में 45 को देखें, जो उसमें शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वह वही लाए हैं इसलिए इन तीन क्लॉजेज में तालमेल बिठाने का प्रयत्न किया गया है।

श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा : मैं श्रीमन्, को फिर से पढ़ कर सुनाए देता हूँ —

'The State Government may, by notification, direct that the provisions of sub section (1) and of clause (d) of the members of the Force charged with the maintenance of public order as may be specified therein, wherever they may be serving, and thereupon the provisions of that sub section shall apply as if for the expression "Central Government" occurring therein, the expression "State Government" were substituted'

तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट किन्हीं भी आफिसर के बारे में नोटिफाई कर सकती है, पुलिस आफिसर के बारे में नोटिफाई कर सकती है।

SHRI SHYAM LAL YADAV I would like to say a word about this clause It is a very important clause and I think the apprehensions of Mr Sakhlecha are mis-founded I would say what happened and why this clause was provided The PAC of Uttar Pradesh some time back was posted in Kashmir and there was a firing in Srinagar The person who was responsible for firing was tried by the Kashmir Government for murder and was convicted by the Kashmir High Court Then the State Government of U P was all the time giving help and State Counsel to that constable and the case went up to the Supreme Court I do not know what happened in the Supreme Court But it has happened that the Provincial Armed Constabulary either at the instance of the Central Government or at the instance of the

different State Governments are going to help in different parts of the country and if the PAC constables performing their duties in different parts of the State are left at the mercy of the State Government, and if there is no protection, I think from that point of view the word 'Force' has been used. So, the word 'Force' means the Armed Force of a State Government and it does not apply to a police officer of any rank. It applies only to the Armed Police, i.e. Provincial Armed Constabulary or some other name given to the Armed Police. So, this clause is very relevant and we have already provided for this in clause 45. So, I think the State PAC does deserve this protection.

MR DEPUTY CHAIRMAN The question is

6 That at page 86—

(1) the existing sub clause (2) be renumbered as sub clause (4) thereof,

(ii) before sub clause (4) as so renumbered the following sub clauses (2) and (3) be inserted namely—

(2) No court shall take cognizance of any offence alleged to have been committed by any member of the Armed Forces of the Union while acting or purporting to act in the discharge of his official duty, except with the previous sanction of the Central Government

(3) The State Government may, by notification, direct that the provisions of sub clause (2) shall apply to such class or category of the members of the force charged with the maintenance of public order as may be specified therein, wherever they may be serving, and thereupon the provisions of that sub section will apply as if for the expression 'Central Government' occurring therein the expression 'State Government' were substituted

The motion was adopted

MR DEPUTY CHAIRMAN The question is

That clause 197 as amended stand part of the Bill

The motion was adopted

Clause 197, as amended, was added to the Bill

Clause 198 to 199 were added to the Bill

Clause 320—Compounding of offences

SHRI NAWAL KISHORE Sir, I move

33 That at page 125 line 7, after the words in the third column the words or their legal representatives in case of such person's death or disappearance be inserted

34 That at page 126 line 5, after the words in the third column the words 'or their legal representatives in case of such person's death or disappearance,' be inserted

The questions were proposed

SHRI NAWAL KISHORE I know that Mr Mirdha will not accept them in spite of their genuineness and validity. Clause 320 says

The offences punishable under the sections of the Indian Penal Code specified in the first two columns of the Table next following may be compounded by the persons mentioned in the third column of that Table

I only want to add the words or their legal representatives in case of such person's death or disappearance. I would like to point out that the intention of this Clause is being furthered by my amendments and I cannot see what objection he could have. I also see that a very important Member of the Joint Committee, Mr. B. R. Shukla, has given a note of dissent in this very connection. Even though the Report is unanimous by the majority Mr Shukla has been obliged to give a note of dissent in this regard. Under these circumstances I can only hope against hope that Mr Mirdha will see his way to accept these amendments of mine.

SHRI SHYAM LAL YADAV They are very simple amendments

SHRI RAM NIWAS MIRDHA We discussed this very thoroughly in the Select Committee and as I said earlier various difficulties will arise by accepting this.

[Shri Ram Niwas Mirdha] *

Therefore it is really not possible for me to accept these amendments.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

33. "That at page 125, line, 7, after the words 'in the third column' the words 'or their legal representatives in case of such person's death or disappearance' be inserted."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is

34. "That at page 126, line 5, after the words 'in the third column' the words 'or their legal representatives in case of such person's death or disappearance' be inserted."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 320 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 320 was added to the bill.

Clauses 321 to 343 were added to the Bill.

Clause 344—Summary procedure for trial for giving false evidence

SHRI SHYAM LAL YADAV. Sir, I move:

35. "That at page 135,

(i) in line 37, for the words 'Session Judge' the words 'Court of Session' be substituted, and

(ii) in lines 39 to 41 the words 'had made on oath a statement which had substantially contradicted his previous statement on oath recorded under section 164 or section 200 or he' be deleted."

The question was proposed.

SHRI SHYAM LAL YADAV: Sir, I would like to say just one word. This clause deals with summary procedure for trial for giving false evidence. The portion I want to delete by my amendment

was agreed upon to be deleted by the Select Committee but inadvertently that portion has been kept in here. I think this portion should be deleted. And I have just made one consequential change. I think the Government would accept this.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: I accept this amendment.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

35. "That at page 135,

(i) in line 37, for the words 'Session Judge' the words 'Court of Session', be substituted, and

(ii) in lines 39 to 41, the words 'had made on oath a statement which had substantially contradicted his previous statement on oath recorded under section 164 or section 200 or he' be deleted."

The motion was adopted

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 344, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 344, as amended, was added to the Bill.

Clauses 345 to 353 were added to the Bill.

Clause 354—(Language and contents of judgment)

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: Sir, I move—

7. "That at page 139:—

(i) the existing sub-clauses (4) and (5) be renumbered as sub-clauses (5) and (6), respectively thereof; and

(ii) before sub-clause (5) as so renumbered the following sub-clause (4) be inserted, namely:—

'(4) When the conviction is for an offence punishable with imprisonment for a term of one year or more, but the court imposes a sentence of

imprisonment for a term of less than three months, it shall record its reasons for awarding such sentence, unless the sentence is one of imprisonment till the rising of the court or unless the case was tried summarily under the provisions of this Code."

The question was proposed.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: I would commend this amendment for the consideration of the House because this is a new provision which is included to restrict short-term imprisonment since we find that a large number of persons in jail are there for short terms and it does not serve a useful purpose. That is why this amendment is being brought to restrict the award of short term imprisonments.

श्री बीरेन्द्र कुमार सखलेचा : यह जो संशोधन क्लोज 354 में माननीय मंत्री जी द्वारा पेश किया गया है, उसके सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि जब माननीय मंत्री जी ने 197 क्लोज में संशोधन पेश किया था और जिस समय उसको लिया जा रहा था उस समय मुझे आश्चर्य हो रहा था कि उसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्लोज 197 में जो अमेंडमेंट था उसमें आर्ड फोर्स की बात की गई जब कि वह पुलिस फोर्म से सम्बन्ध रखता है। अब यह जो अमेंडमेंट माननीय मंत्री जी सदन के सामने लाये हैं उसका असर यह होगा कि जज के अपने जजमेंट के वक्त यह एनाउन्स करना पड़ेगा और उसके साथ ही साथ रीजन्स भी देने पड़ेंगे कि उसने तीन साल या एक साल की सजा क्यों दी ?

किस कारण जो जुर्म एक साल की सजा से पनिशेबल है उसमें तीन महीने में कम की सजा दे रहे हैं। जूरिसप्रूडेंस और न्याय व्यवस्था में यह कही नहीं है कि किसी जुर्म में 10 मान की सजा की व्यवस्था है मजिस्ट्रेट समझता है कि एक साल की सजा या तीन

महीने की सजा देने की आवश्यकता है तो उससे एक्सप्लेनेशन मांगा जाय।

"(4) When the conviction is for an offence punishable with imprisonment for a term of one year or more, but the court imposes a sentence of imprisonment for a term of less than 3 months, it shall record its reasons for awarding such sentence "

ऐसा कहीं आज तक नहीं रहा। जब आपने दस साल की सजा, चार साल की सजा या 5 साल की सजा रखी है तो इसका मतलब यही है कि 5 साल की सजा देनी चाहिए, चार साल की सजा देनी चाहिए। कम दे यह जज का डिस्क्रिशन है लेकिन उस सिलसिले में रीजन्स देने को कम्पेल करने का कोई कारण मुझे नहीं दिखाई देता। उसका यह अर्थ भी लगाया जायगा कि उन्हें ज्यादा सजा देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन मांगना उचित नहीं है, यह जूरिसप्रूडेंस के सिद्धान्त के खिलाफ है और इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

That at page 139:—

(i) the existing sub-clauses (4) and (5) be renumbered as sub-clauses (5) and (6), respectively thereof; and

(ii) before sub-clause (5) as so renumbered the following sub-clause (4) be inserted, namely:—

"(4) When the conviction is for an offence punishable with imprisonment for a term of one year or more, but the court imposes a sentence of imprisonment for a term of less than 3 months, it shall record its reasons for awarding such sentence, unless the sentence is one of imprisonment till the rising of the court or unless the case was tried summarily under the provisions of this Code."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That clause 354, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 351, as amended, was added to the Bill.

Clauses 355 to 372 were added to the Bill.

Clause 373—*Appeal from orders requiring security or refusal to accept or rejecting surety for keeping peace or good behaviour*

SHRI SHYAM LAL YADAV: Sir, I move:

36. "That at page 145, lines 26 to 29 be deleted."

The question was proposed.

SHRI SHYAM LAL YADAV : This is a consequential amendment which has already been accepted in clause 116. So, I think my amendment should be accepted, because it is consequential.

SHRI NAWAL KISHORE: On a point of order. You had kindly said that those amendments which were negative in nature would not be taken up, but here Mr. Yadav's amendment says that lines 26 to 29 be deleted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is part of the clause and not the entire clause. When you gave your amendment you should have been very careful. The amendment of Shri Shyam Lal Yadav. The question is:—

36. "That at page 145, lines 26 to 29 be deleted."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The question is:

"That clause 373, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 373, as amended, was added to the Bill.

Clauses 374 to 388 were added to the Bill.

Clause 389—*Suspension of sentence pending the appeal; release of appellant on bail.*

SHRI SHYAM LAL YADAV: Sir, I move:

37. "That at page 151,—

(i) lines 3 to 5 be deleted; and

(ii) in line 7, for the words 'for a term exceeding' the words 'for a term not exceeding' be substituted."

The question was proposed.

SHRI SHYAM LAL YADAV: It covers the question of bail. When a person is convicted under a bailable offence, he will be granted bail. If it is a non-bailable offence and the sentence is for not exceeding three years and if he was on bail, he should be allowed bail. I think that is the purpose of the Bill as proposed by the Joint Committee, but in drafting some changes were introduced. I think the Government will agree to this.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : Yes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:—

37. "That at page 151,—

(i) lines 3 to 5 be deleted; and

(ii) in line 7, for the words 'for a term exceeding' the words 'for a term not exceeding' be substituted."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:—

"That clause 389, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 389, as amended, was added to the Bill.

Clauses 390 to 406 were added to the Bill.

Clause 407—Power of High Court to transfer cases and appeals.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: Sir, I move:

8. "That at pages 157 and 158, lines 23 to 49 and 1 to 18, respectively, be deleted."

The question was proposed.

श्री नवल किशोर : श्रीमन्, वैसे तो मिर्धा साहब ने इसका जवाब जब अपनी डिबेट बाइन्डअप की थी उसी वक्त दे दिया था, लेकिन मुझे अफसोस यह है कि मैं उन के जवाब से कंविस् नहीं हो पाया। मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है कि एजर्नमेंट प्रोमीडिस को आप रखें या न रखें, लेकिन मैं एक सिधांत के आधार पर इस का विरोध करना चाहता हूं और अच्छा यह होता कि हमारे मिर्धा साहब इस अमेंडमेंट को खुद न पेश करते। अगर उन को इस को पेश करना ही था, पास कराना ही था तो ओम् मेहता साहब से कह कर इस को मनीपुलेट करा लेते और किसी ऐसे आदमी से इस को पेश करवाने जो कि कमेटी का मेम्बर न होता।

श्री ओम् मेहता : मैं कुछ मनीपुलेट नहीं करता हूं।

श्री नवल किशोर : मनीपुलेट शब्द मैं ने बड़े अच्छे मायनों में इस्तेमाल किया है और संसदीय मंत्री होने के नाते ओम् मेहता साहब से बड़ा मनीपुलेटर कोई और हमारे यहां है नहीं। मिर्धा साहब ने कहा कि इस मामले में ला कमीशन की एक बड़ी स्ट्रांग ओपीनियन है कि इस को इस में से हटा दिया जाय। श्रीमन्, अबतक हर संशोधन में न मानने की एक ही दलील थी हर मामले में यह कहा गया कि इस मामले में कमेटी ने बड़े गौर से विचार विनिमय किया और कमेटी ने उस के बाद ही यह फैसला किया है। हमेशा उन का यह आर्गुमेंट था। फिर ला कमीशन की रेकमेंडे-

शन भी तो कमेटी के सामने थी और उस के बावजूद भी ज्वायंट सेलेक्ट कमेटी ने एक फैसला किया और उस में माननीय मिर्धा साहब भी शामिल थे। वह फैसला एक मत से था। उस के बाद श्रीमन्, यह अमेंडमेंट पेश हो, मुझे इस में केवल एक ही आपत्ति है कि ज्वायंट सेलेक्ट कमेटी दोनों हाउसेज को रेप्रेजेंट करती है, अगर वहां कोई यूनानिमस फैसला हो जाय इतनी बहस के बाद और उस के बाद उसे बदलने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई अमेंडमेंट आये, यह मैं समझता हूं कि कोई अच्छा कंवेशन नहीं है। मिर्धा साहब इस बात को ध्यान में रखने हुए इस को प्रेस न करें तो ज्यादा अच्छा है।

SHRI SHYAM LAL YADAV: I would like to say that I associate myself with the observations made by Shri Nawal Kishore. This was a decision arrived at by the Joint Committee at great length and after great discussion for several days at several sittings. The Ministry was very much persistent with its desire to do away with this provision. But ultimately by argument, the Committee was able to convince the hon. Minister and he agreed to this proposal, that is when a transfer application is moved before the court before the defence closes its case, he should make an application. It says—

"If in any inquiry under Chapter VIII or in any trial, any party interested intimates to the Court at any stage before the defence closes its case that he intends to make an application under this section, the Court shall, upon his executing, is so required, a bond without sureties of an amount not exceeding two thousand rupees that he will make such application within a reasonable time to be fixed by the Court, adjourn, subject to the payment by the party seeking such adjournment such costs as may be fixed by the Court, the case for such a period as will afford sufficient time for the application to be made and an order to be obtained thereon:"

[Shri Shyam Lal Yadav]

What I would like to submit is that all these conditions were imposed at the instance of the hon. Minister—I must say—and now we are surprised that he has introduced an amendment doing away with all these things I think this will harm the course of justice and people will lose confidence in the courts. They will be left without any mercy, remedyless, to go and obtain transfer of cases from courts which will hurry up with the trial, conclude the trial, immediately convict them and send them to jail and the transfer application will become useless. I submit, there is no reason. I have reason to oppose the amendment to clause 354 also. But I refrained because the Committee did not give any opinion on that clause that the imposition of a minimum sentence is necessary. But here the Committee has given a definite decision. I would like to submit that all these things were done at the great insistence of the Government that these conditions should be imposed so that no person should be encouraged or should feel it easy for moving the transfer for delaying the case by trial.

I think sufficient impediments have been placed in the course of such hurried actions and there will not be any undue delays. These provisions are for extreme cases. There are very rare transfer applications but the law provides for such cases. Therefore, there is no justification for amending and these provisions. I would still request the Minister that he should consider this fact because this matter will raise again a hue and cry in the two Houses because it is a very important advantage to the accused person if you remove this defect.

One thing more I hope the existing provisions do not contain so much impediments in the way of moving transfer applications. But here we have placed several other impediments, more than what is existing today. Therefore, let us see the working of this provision for some time and if afterwards this provision is misused they can bring in another Bill.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: Sir, it is after great hesitation, but after very serious consideration, that I thought fit to bring this amendment. It is very true

that normally it should not take place because the Select Committee had unanimously adopted it. But even in the Select Committee I expressed hesitation and some of the suggestions that were incorporated were as a result of discussions that took place in the Committee. Why I have brought it is because this clause has a long history. Many times attempts have been made to amend it because it was thought to be obstructive of justice. If you bear with me for a short time, I would like to read out some extracts from the Law Commission's report. It says:—

"The Statement of Objects and Reasons for the 1932 Bill mentioned that:

"The practical working of this new procedure has been carefully observed by Government over a considerable period, and they have come to the conclusion that it leads itself to grave abuse and is calculated to defeat the ends of justice."

"In a judgment of the Calcutta High Court, it was forcefully observed:—

"The position created by section 526(8) is truly amazing, one effect being that no accused persons can be convicted except with his own consent. No discretion is given to the court by the section. If the accused notifies his intention to make application to the High Court for transfer, the trial must be adjourned immediately. There is no limit to the number of such notifications. It may be given during the course of any trial . . . The abuse of process which sub-section (8) makes possible obviously may be aggravated to almost any extent, where there is a joint trial and each accused person is represented by a different pleader."

So, the report goes on to give more arguments and reasons why this type of amendment is necessary.

So, Sir, this is the background why I have thought it fit to bring this amendment. This is a good amendment. It will speed up the processes of trial. Many times people with resources resort to these stratagems because a poor man who is not properly represented would not resort to these

[Shri Ram Niwas Mirdha.]

strategems for extending the trial. It is only the resourceful people, people with money, people with legal knowledge, resort to such things and I think we should not be a party to such procedural stratagems which might indefinitely postpone the trial. Therefore, I would request the House to accept the amendment.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

8. "That at pages 157 and 158, lines 33 to 49 and 1 to 18, respectively, be deleted."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That clause 107, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 107, as amended was added to the Bill.

Clause 108—Power of Sessions Judge to transfer cases and appeals

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: Sir, I move:

9. "That at page 158, lines 28 and 29, for the figures brackets and word '(7), (9), (10) and (11)' the figures, brackets and word '(7) and (9)' be substituted." Sir, this amendment is only consequential to the change made earlier.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

9. "That at page 158, lines 28 and 29, for the figures brackets and word '(7), (9), (10) and (11)' the figures, brackets and word '(7) and (9)' be substituted."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That clause 408, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 408, as amended, was added to the Bill.

Clauses 409 to 410 were added to the Bill.

Clause 111—Making over or withdrawal of cases by Executive Magistrates

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: Sir, I move:

10. "That at page 159, line 11, the words 'of which he has taken cognizance' be deleted."

The question was proposed.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: Sir, this is merely a drafting change.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

10. "That at page 159, line 11, the words 'of which he has taken cognizance' be deleted."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:—

"That clause 111 as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 411, as amended, was added to the Bill.

Clauses 412 to 436 were added to the Bill

Clause 437—When bail may be taken in case of non bailable offence

SHRI SASANKASEKHAR SANAYI: Sir, I move:

21. "That at page 166 after line 59, the following be inserted, namely:—

"Provided further that bail shall be granted as a rule and that refusal of bail shall be an exception and as such refusal shall always be founded on reasonable grounds."

28. That at page 166, line 36, after the word 'investigation' the words 'or that he may abscond or tamper with evidence' be inserted."

The questions were proposed.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL Sir, in the amendment I have suggested that there should be no impediment to the grant of bail and I want to enlarge the scope by making part of the law the fear that he may abscond or tamper with evidence. These are those outmoded medieval concepts. I have already made my submission at the earlier stage. I do not know whether Mr. Mudha is trying to find his way to accepting it or not.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA Sir, this amendment if accepted would completely obliterate the difference between bailable and non-bailable offences. Even as it is, we have liberalised the provisions regarding bail. For example, formerly bail was not given because someone was needed for identification parade and things of that nature.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL In the Murtu Conspiracy case Justice Hutchinson observed that bail should be the rule and refusal the exception. That was in the British days. Many British judges held that view. Now at the time there was no fundamental right of liberty. Now that we have fundamental rights of liberty even without obliterating the difference between bailable and non-bailable offences you can make a provision that bail should be the rule and refusal should be the exception and the grounds for refusal should be stated.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA Well, Sir,

SHRI V. K. SAKHLFCHA Sir, regarding this last portion that bail should be the rule.

MR DEPUTY CHAIRMAN This is an after thought. He had spoken and the Minister was replying.

SHRI V. K. SAKHLFCHA He was speaking on this provision मेरा यह निवेदन है कि बेल के प्राविजन के बारे में यह केवल एक हाई कोर्ट का डिस्क्रिशन नहीं है अनेक हाई कोर्टों के डिस्क्रिशन है

MR DEPUTY CHAIRMAN You cannot make a speech in the middle of the Minister's reply.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA The hon. Member is supporting the amendment and supporting the judicial pronouncement which was quoted by Shri Sanyal. Whatever judicial pronouncements are there which are very much in favour of giving bail we respect them all. But this amendment would leave no discretion to the court at all. Now the court has discretion to decide in the light of the various judicial pronouncements. Secondly, it will obliterate the difference between bailable and non-bailable offences. There are enough safeguards provided in the Bill.

MR DEPUTY CHAIRMAN The question is—

21 That at page 166 after line 39 the following be inserted namely—

Provided further that bail shall be granted as a rule and that refusal of bail shall be an exception and such refusal shall always be founded on reasonable grounds.

The motion was negatived.

MR DEPUTY CHAIRMAN The question is—

38 That at page 166 line 36 after the word investigation the words or that he may abscond or tamper with evidence be inserted.

The motion was negatived.

MR DEPUTY CHAIRMAN The question is—

That clause 417 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 437 was added to the Bill.

Clauses 438 to 463 were added to the Bill.

Clause 484—Repeal and savings.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA Sir, I move.

11 That at page 181 lines 3 and 4, the words and nothing in this Code shall

apply to any such prosecution be deleted.

The question was proposed.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: Sir, the amendment is of a drafting nature

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is—

“That at page 181, lines 3 and 4, the words ‘and nothing in this Code shall apply to any such prosecution’ be deleted.”

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is—

“That clause 484, as amended, stand part of the Bill”.

The motion was adopted.

Clause 484, as amended, was added to the Bill.

The First Schedule and the Second Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: Sir, I move—

“That the Bill, as amended, be passed”

The question was proposed

श्री रमेशी लाल चौधरी (उत्तर प्रदेश)
उपसभापति महोदय, यह बिल ज्युरिस्प्रूडन्स में ताल्लुक रखता है। जिस समय यह ऐक्ट पहले बना था उस समय ज्युरिस्प्रूडन्स का जो मतलब था वह दूसरा था। आज के वक्त में जब समाजवाद आया है तो ज्युरिस्प्रूडन्स की डैफिनिशन और ज्युरिस्प्रूडन्स भी साथ साथ बदलता जा रहा है। मुझे दुख है, आज के बदलते हुए समय के अनुसार इस बिल में प्राविजन नहीं किया गया है। जहाँ पर देखो तहाँ पर पावर बढ़ाया गया है, राइट्स बढ़ाए गए हैं, चाहे मेजिस्ट्रेट्स के हों

चाहे पुलिस आफिसर्स के हों, चाहे ममरी ट्रायल्स हों। श्रीमन्, मैं यह इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज ऐसा वक्त आ गया है कि हर आदमी अपने राइट और अपने ताकत की मांग करता है, इय्टी की मांग नहीं करता है। आज हम भुक्तभोगी हैं। आज जरा देश में रिपोर्ट मंगा कर देख ले, धारा 107 में 109 में कितने गरीब हरिजन और बेजुबान लोग बंद हैं। जहाँ पुलिस बाराज हुई, फौरन धारा 107 में उठा कर बंद कर दिया। तो आपने पुलिस वालों के ऊपर ऐसी कार्ड नहीं लगाई कि अगर आप गलत हरिजन बंद करेंगे तो उनके ऊपर भी एक्शन हा मकेगा। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आज छोटे छोटे पढ़े लिखे हरिजनों की ज़िदगी बर्बाद की जा रही है। हमारे जिले में एक विद्यार्थी था, हाई स्कूल सेकेंड डिविजन में पास करके इंटरमीडिएट में पढ़ना चाहता था। लोग नागज थे, उन्होंने पुलिस में मिलकर आर्म्स ऐक्ट में उसको रख दिया जमानत के लिए। आर्म्स ऐक्ट में आइडेंटिफिकेशन की कार्ड वान नहीं आती है लेकिन दरोगा जी ने लिख दिया कि यह मामला आइडेंटिफिकेशन का है इसलिए 4 महीने—जुलाई, अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर, वह बेचारा जेल में बंद रहा। 4 महीने के बाद जब छूट कर आया तो स्कूल में नाम नहीं लिखा गया, उसका नाम काट दिया गया। दरोगा जी के ऊपर इसके बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं हुई हालांकि मैंने बहुत एस०पी० से कहा। आज भी दरोगा वही मौजूद है। दरोगा यह कह रहा है, अब के तुम छूट गए लेकिन आगे तुमको डकैती में धरेगे।

तो श्रीमन्, आपने पावर तो बढ़ाया है लेकिन यह पावर, मुझे डर है, हरिजनों के ऊपर, गिरे हुए तबकों के ऊपर

[श्री गणेशी लाल चौधरी]

इस्तेमाल किया जाएगा। तो यह जो नया समाजवाद, नयी रोशनी आई है—हमारी प्रधान मंत्री इन्दिरा जी नयी रोशनी लाई है—इस रोशनी में आप आज यह कानून बदल रहे हैं तो इसमें राइट्स एन्ड पावर्स सबकी बढ़ा रहे हैं लेकिन उनकी ड्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं, यह खतरा है उन लोगों के लिए जो देश के गिरे हुए लोग हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज समाजवाद में एक धारणा बन रही है देश में लोगों की और गरीबी हटाओ की एक धारणा बन रही है। उस में हरिजनों की हानि होगी। मैं एक दाँठे में उसको आपके सामने कहना चाहता हूँ, क्या समाजवाद की डेफिनिशन, समाजवाद की परिभाषा, जो आपने की है उसकी तह में आप यह कानून बना रहे हैं तो—

‘ईश्वर अल्ला तेरा नाम पूरा पैसा आधा काम, तो श्रीमान्, आज जो समाजवाद आ रहा है, उस में आप गरीबों के लायक कानून बनाइये क्योंकि आप मजिस्ट्रेटों को जो पावर देने जा रहे हैं उसमें थोड़े गरीब लोग फिसल रहे हैं। मैं आप में माग करूँगा कि आप रिपोर्ट मगवाइये कि आज 107 के अन्तर्गत कितने हरिजन लोग बन्द हैं, आज कितने 109 के अन्तर्गत हरिजन बन्द हैं। आज दूसरे लोगों के ऊपर यह धारा—लागू नहीं की जाती है। मैंने इस सम्बन्ध में कोई मशोधन नहीं दिया है और सदन थोड़ी देर में इस बिल को पास कर देगा, लेकिन मुझको इस चीज से बड़ी निराशा हो रही है कि इस चीज से इम्प्रूवमेंट आने वाला नहीं है। इस-लिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ

कि उनका जो समाजवाद का नारा है, गरीबी हटाओ का नारा है, वह बिल्कुल बेकार हो गया है।

श्री विरेन्द्र कुमार सखलेचा उप सभा-पति जी आप इस बिल को पारित करने जा रहे हैं। क्रिमिनल प्रोमिजर कोड बिल के सम्बन्ध में सदन के सामने कई मशोधन रखे गये ताकि यह बिल और अच्छा हो जाय, लेकिन उनके सम्बन्ध में जो उत्तर मिले, उसमें हम सब लोगों को निराशा हुई। मुझे यह बात बड़े दुःख के साथ कहनी पड़ रही है कि जब मिलेक्ट कमेटी में सब बात नय हो चुकी है, उसका ही लास्ट वर्ड है तो फिर इस सदन में अमेन्डमेंट मूव करना, उसे इस बात का अधिकार देना और इस सदन द्वारा विचार करने का जो प्रावधान है, वह कोई अर्थ नहीं रखता है। यह बात सही है कि मिलेक्ट कमेटी में मंत्री जी की सहायता के लिए अधिकारिगण रहते हैं, पर सदन के अन्दर तो उन्हें स्वयं जवाब देना पड़ता है और स्वयं निर्णय करना पड़ता है। लेकिन हम यह आशा करते हैं कि मंत्री जी उचित मशोधन व वारे में अपनी राय दे सकते हैं और उन्हें स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जो बात हमने अनुभव की वह यह है कि जो महत्वपूर्ण प्रावि-जन्म है, उनके सम्बन्ध में जो आरग्यु-मेंट्स दिये गये थे, उनका कोई उत्तर नहीं दिया गया। वेल के बारे में, एफ० आर० आई० के बारे में, जजमेंट के बारे में, ट्रांसफर के प्राविजन के बारे में कोई उचित उत्तर नहीं दिया गया और आप इस बिल को पारित कर रहे हैं। आज आप का बहुमत है, आप इसको पारित कर सकते हैं, लेकिन मैं इस सम्बन्ध में यह आग्रहामन चाहता हूँ, जैसा कि आपने अपने जवाब

के अन्दर कहा कि आप एफ० आर० आई० के प्राविजनों में किसी प्रकार का संशोधन मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है और उसके अन्तर्गत, मैं आशा करूँगा कि केन्द्रीय सरकार तथा स्टेट सरकारों को आप यह निर्देश देंगे कि जो अधिकारी इसका प्रयोग करते हैं वे इसका दुरुपयोग न करें क्योंकि आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो सब इम्पेक्टर हैं थाने के हैड कास्टेबिल हैं वे एफ० आर० आई० की रिपोर्ट को दर्ज कराने के अधिकारी होते हैं और ट्रायल के समय यह रिपोर्ट बहुत महत्व रखती है। इस नाते मैं यह चाहता हूँ कि पुलिस रेगुलेशन बनाने वक्त आप यह देखेंगे कि जो सब इस-पेक्टर हैं, हैड कास्टेबिल हैं, जिम को आप यह अधिकार देने जा रहे हैं, वे जनता के अधिकारों का पूरी तरह से संरक्षण करें और वे अपने इस अधिकार का दुरुपयोग न करें। अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है तो आप डिपार्ट-मेन्टली उसके खिलाफ ऐक्शन ले सकते हैं ताकि वे ट्राइल के समय केस के सम्बन्ध में कोई गड़बड़ी न कर सकें। बेल बिना कारणों के रीफ्यूज न की जाय, बेल एज ए रूल, हाई कोर्ट के जो नियम हैं, हाई कोर्ट की जो रूलिंग है, उस हिसाब से लोगों को बेल मिले। लोगों को 107 के अन्तर्गत तंग न किया जाय। यद्यपि आपने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को पावर दे रखी है, तो आप को इस बात की भी व्यवस्था करनी चाहिये कि वह ट्रायल को कम्प्लीट करे और एक डेढ़ महीने के अन्दर उसका फैसला दे दे। 107 के अन्तर्गत उन्हें इस प्रकार की ड्यूटी पर न भेजा जाय।

यह जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बिल है यह जनता के लिए एक महत्वपूर्ण

बिल है क्योंकि क्राइम ट्राइल में जनता को इस बिल द्वारा वास्ता पड़ता है। आप इस बिल को पारित करने जा रहे हैं, लेकिन जिन प्वाइंटों के बारे में हमने आपका ध्यान खींचा है, जनता को संरक्षण देने के बारे में जो सुझाव आपको दिये, उनको आपने नहीं माना और अब आप इस बिल को पारित करने जा रहे हैं। लेकिन मैं अंत में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस बात का ख्याल रखा जायेगा कि जो इसमें प्राविजन हुए हैं उनका दुरुपयोग न हो और एफ० आर० आई०, बेल, केस का प्रापर ट्रायल, लोगों को न्याय मिले, इन सब बातों का ख्याल रखा जायेगा और इसी उद्देश्य से हम इस बिल को पास करें, यही मैं आशा करता हूँ।

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, यह कहना अनुचित है कि सरकार ने यह विधेयक केवल बहुमत के आधार पर पास कराने की कोशिश की है। प्रवर समिति में जो भी बातें उठाई गईं उन पर पूर्ण विचार किया गया। कभी भी प्रवर समिति में कोई भी बात बहुमत के आधार पर मनवाने की कोशिश नहीं की गई। यहाँ पर भी सैयद अहमद साहब ने एक संशोधन दिया, एक मसले पर हमारा ध्यान आकृष्ट किया, उसे हमने स्वीकार किया, और भी कई संशोधन स्वीकार किए गए हैं। इसलिए यह कहना कि सदन में जो बातें कही गई हैं या जो संशोधन लाए गए उनको केवल बहुमत के आधार पर रद्द कराने की कोशिश की गई वह न्यायपूर्ण नहीं है, यही मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है। कई बातें ऐसी हैं और कई संशोधन ऐसे हैं जिनको स्वीकार करने में असमर्थ था क्योंकि उन प्रावधानों की कई राज्यों ने अपने नियमों में डाल रखा है, जैसा मुल्ला साहब ने कहा। मैं आशा करता हूँ कि जो इस विधेयक की

[श्री राम निवास मिर्धा]

भावना है और जो भावनाएं सदन में माननीय सदस्यों ने व्यक्त की हैं उन पर राज्य सरकारें विचार करेगी और जो भी हम इस विधेयक के द्वारा न कर सकें या न करना चाहें क्योंकि उसमें विधेयक को बहुत ही कुठित करने की स्थिति पैदा हो जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य सरकारें और प्रशासन माननीय सदस्यों की इन भावनाओं पर विचार करेगी और जो कमियां रह गई हैं जो पूरी की जा सकती हैं वे नियमों के द्वारा पूरी करने की कोशिश करेगी और केन्द्रीय सरकार भी इसमें जो सहायता दे सकेगी वह देगी और मेरा विश्वास है कि राज्य सरकारों के सह-

योग से हम ऐसे क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था कर सकेंगे जो समयानुकूल हो।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11-00 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at fifty-seven minutes past four of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 14th December, 1972.